www.dainikjayantnews.com
कोटद्वार, शनिवार
22 अगस्त 2026
वर्ष: 49
अंक: 110 पृष्ठ: 6
मूल्य: 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

अमरीका नहीं जा पाएंगे तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी

- केंद्र का झटका, अमेरिका जाने की नहीं मिली परमीशन

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को अमेरिका जाने की केंद्र से मंजूरी नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। सीएमओ के

मुताबिक, रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाला तेलंगाना राइजिंग प्रतिनिधिमंडल अमेरिका दौरा नहीं कर सकेगा। विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक आधार पर क्लियरेंस देने से इनकार किया है। रेवंत रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं। उन्हें अमेरिका के बोस्टन जाना था और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटना था, लेकिन अब वे 23 अगस्त को सीधे हैदराबाद लौटेंगे। हालांकि, सीएम रेड्डी ने अधिकारियों को अमेरिका जाए बिना वहां के संस्थानों के साथ सभी एमओयू और साझेदारी समझौते पूरे करने के निर्देश दिए हैं। **पहले से तय था यूके और यूएस का दौरा-** रेवंत 20 अगस्त को लंदन पहुंचे थे। यूके दौरे में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और लंदन बिजनेस स्कूल के कार्यक्रम शामिल थे। उन्हें एमिरेट्स स्टेडियम में फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रम में भी जाना था।

अखिलेश-मायावती को योगी सरकार ने दी बुलेट प्रूफ जैकेट

- पहली बार 52 नेताओं को बांटी, इनमें राजभर, नंदी, अपर्णा यादव का भी नाम

लखनऊ (एजेंसी)। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव, मायावती समेत 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी। इनमें 11 कैबिनेट मंत्री भी हैं। मंत्री संजय निषाद, नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी', ओपी राजभर, अपर्णा यादव को जैकेट मिल गई है। बुलेट प्रूफ जैकेट यूपी सरकार के सुरक्षा मुख्यालय ने खरीदी है। एक बुलेट प्रूफ की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। मंत्री

संजय निषाद ने बुलेटप्रूफ जैकेट मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा- उन्हें बुलेटप्रूफ जैकेट पहनना ही नहीं आता है। अब तक इसे पहनना नहीं सिखाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा 2027 को देखते हुए सरकार ने एहतियातन यह फैसला लिया है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब नेताओं को बुलेटप्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई है। पहले चरण में 8 जबकि दूसरे चरण में अब 44 नेताओं को जैकेट बांटी गई है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर बुलेट प्रूफ जैकेट बांटने की वजह का खुलासा नहीं किया।

कांग्रेस को घेर रही बीजेपी के गढ़ में ही हो गया 'खेला'

- नागपुर नगर निगम में वंदे मातरम के दो अंतरे गाने पर विवाद

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा शासित नागपुर नगर निगम की आम सभा की बैठक के दौरान एक प्रशासनिक चूक सामने आई है। बैठक की शुरुआत में पारंपरिक रूप से गाए जाने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम के दौरान केवल दो ही अंतरे गाए गए, जबकि केंद्र

सरकार के हालिया निर्देशों के अनुसार इसके सभी अंतरों का पूर्ण गायन किया जाना अनिवार्य है। बता दें कि वंदे मातरम् के गायन को लेकर यह खबर ऐसे समय में सामने आई है, जब हाल ही में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में वंदे मातरम् के केवल दो अंतरे गाने पर भाजपा और उसके सहयोगियों ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे की तीखी आलोचना की थी। विडंबना यह है कि खुद भाजपा शासित नागपुर नगर निगम की बैठक में भी केवल दो ही अंतरे गाए गए। वंदे मातरम् को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सख्त निर्देश हैं।

तीन साल नहीं अब एक साल की वकालत करके भी बन सकेंगे जज

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,जज बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। निचली अदालतों में जज बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मई 2025 के फैसले में संशोधन करते हुए एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 साल की अनिवार्य वकालत की शर्त को घटाकर 1 साल कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने 2-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाते हुए समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उम्मीदवारों के

लिए परीक्षा में बैठने हेतु 3 साल की जगह सिर्फ 1 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। इतना ही नहीं जिन न्यायिक परीक्षाओं के नोटिफिकेशन 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच जारी होंगे, उनके लिए यह अनुभव अनिवार्य नहीं होगा। यानी इस अवधि में बिना अनुभव वाले उम्मीदवार भी परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि इस बीच (बिना अनुभव के) चुने गए उम्मीदवारों को सीधे जज नहीं बनाया जाएगा। वे पहले 1 साल के लिए ट्रेनी ज्यूडिशियल ऑफीसर के रूप में काम करेंगे और उन्हें 1 साल की स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप से गुजरना होगा।

1 अप्रैल 2027 से लागू होगा नया नियम

बता दें कि जिन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2027 या उसके बाद जारी होंगे, उन पर नया संशोधित नियम (1 साल के अनुभव वाला) पूरी तरह लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मई 2025 में बिना किसी ट्रांजिशन पीरियड के अचानक 3 साल की प्रैक्टिस का नियम लागू कर देने से नए लॉ ग्रेजुएट्स और युवा वकीलों के सामने भारी मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जज बनने के लिए वकालत के पेशे का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन इस नियम से युवाओं को अचानक असुविधा नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के सीधे जज बनने की परीक्षा पर रोक लगाते हुए कम से कम 3 साल की वकालत की शर्त अनिवार्य कर दी थी। इसके बाद जुलाई 2025 में अदालत ने इस फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में अब नए फैसले के तहत कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए 3 साल की शर्त को 1 साल कर दिया है और बीच के समय के लिए विशेष राहत दी है।

असम-मेघालय बॉर्डर पर भारी तनाव

- शिलॉन्ग में केयूसी की रैली के दौरान जमकर हंगामा
- असम के लोगों से मारपीट से शुरू हुआ था विवाद

शिलॉन्ग (एजेंसी)। बुधवार को मेघालय में असम के लोगों से मारपीट से शुरू हुआ विवाद अब मेघालय के कई राज्यों तक पहुंच गया है। मेघालय में सरकारी संपत्तियों पर आगजनी और पेट्रोल बम फेंकने की घटनाएं सामने आई हैं। असम ने भी मेघालय से लगी अपनी सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी है। बुधवार को मेघालय के शिलॉन्ग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन की रैली के दौरान असम के लोगों के साथ मारपीट कर उनके वाहनों को आग लगा दी गई थी। हिंसा में 31 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया था, जिनमें ज्यादातर असम के नंबर की थीं। इसके बाद मेघालय के कई जिलों में हिंसा की छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई थीं। हिंसा के शिकार ज्यादातर लोग असम के हैं। इसके विरोध में गुरुवार को गुवाहाटी के टैक्सी चालकों ने नेशनल हाईवे-27 पर आवाजाही रोक दी थी।

शिलॉन्ग में पुलिस चौकी पर हमला

हालांकि, शिलॉन्ग में गुरुवार को दिन भर हालात सामान्य रहे। लेकिन, रात करीब 9.30 बजे नोंगमेंसोंग पुलिस चौकी पर अज्ञात लोगों ने पेट्रोल बम फेंक दिया। बम चौकी के अंदर गिरा और आग लग गई। हालांकि, इस समय इमारत की ऊपरी मंजिल पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे।

25 अगस्त तक तैनात रहेंगी केंद्रीय बलों की 5 कंपनियां

केंद्र ने गुरुवार को मेघालय में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय बलों की पांच कंपनियां तैनात करने को मंजूरी दी। इनमें सीआरपीएफ की चार और रैपिड ऐक्शन फोर्स की एक कंपनी शामिल है। ये कंपनियां 25 अगस्त तक राज्य में तैनात रहेंगी। मेघालय सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों से बचने की अपील की है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने शिलॉन्ग के संवेदनशील इलाकों और राज्य के दूसरे हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारी आगे की हिंसा रोकने की कोशिश कर रहे हैं।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शांति बहाल करने पर सहमत

दोनों राज्यों के बीच तनाव कम करने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। दोनों ने राज्यों में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की बात कही। मेघालय के उप मुख्यमंत्री सियावभालांग धर और असम के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा को बैठक करने की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों मंत्री स्थिति सुधारने, आगे की घटनाएं रोकने, यात्रियों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरी सामान व सेवाओं की लगातार आवाजाही पर चर्चा कर रहे हैं।

जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, यहीं बैठा रहूंगा

धरने पर राहुल गांधी,अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे से दिल्ली के संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल लोहबच की एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वे यहां से हटेंगे नहीं। हालांकि बाद में पुलिस ने अज्ञात

व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इस दौरान राहुल ने साहिल को पैलेट गन से लगे छर्रे दिखाए। उन्होंने कहा, पैलेट गन चलने के सबूत हैं। ये छर्रे साहिल के शरीर से निकले हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है। पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र साहिल घायल हो गए थे।

दिल्ली पुलिस बोली-शिकायत क्राइम ब्रांच को भेजी जाएगी- दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शिकायत पीड़ित ने खुद दी है। 20 जुलाई को दर्ज सभी मामलों की जांच पहले से क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस ने शिकायतकर्ता को बताया है कि उसकी शिकायत भी क्राइम ब्रांच को भेजी जाएगी। वहीं, राहुल गांधी की मांग को सुनने के बाद डीसीपी ने कहा, अभी इस मामले में दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राहुल बोले-शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली

राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं। उन्होंने कहा,जब तक पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक मैं थाने में ही बैठा रहूंगा। फिलहाल थाने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के डीसीपी ऑफिस पहुंचे और पैलेट गन मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

उत्तरकाशी में गर्भवती और नवजात ने तोड़ा दम

हेली सेवा का इंतजार रह गया अधूरा

उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले के मोरी विकासखंड के सीमांत और दुर्गम क्षेत्र से बेहद दुखद खबर सामने आई है। ओसला निवासी अमिना की प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई, जबकि उनके नवजात शिशु ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में मां और नवजात की मौत की खबर से ओसला, गंगाड़ समेत आसपास के गांवों में शोक की लहर दौड़ गई। बताया जा रहा है कि गंगाड़ निवासी शंकर दास उर्फ बब्लू दास की पत्नी अमिना कुछ समय से अपने

मायके ओसला में रह रही थीं। प्रसव के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें बेहतर उपचार के लिए ओसला से गंगाड़ की ओर लेकर निकले, लेकिन रास्ते में उनकी हालत लगातार गंभीर होती चली गई। इसी दौरान अमिना ने दम तोड़ दिया। वहीं, बताया गया है कि नवजात शिशु की भी ओसला में ही मौत हो गई।

प्रसव के बाद बिगड़ी हालत, रास्ते में गई जान

परिजनों के अनुसार प्रसव के बाद अमिना की हालत अचानक खराब हुई थी। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच उन्हें उपचार के लिए ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। रास्ते में ही उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। मां और नवजात की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ग्रामीणों में भी गहरा आक्रोश और दुख है।

दुर्गम रास्तों ने फिर बढ़ाई स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता

इस घटना ने एक बार फिर सीमांत गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं और आपातकालीन परिवहन व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोरी विकासखंड के कई गांव आज भी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है।ग्रामीणों का कहना है कि प्रसव जैसी आपात परिस्थितियों में समय बेहद महत्वपूर्ण होता है।

देश भर में बढ़ गए हैं स्वाइन फ्लू के मामले

- एमपी में महिला की मौत,स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई है। महिला को कोई दूसरी बीमारी नहीं थी। मृतक की पहचान सरोज नागर (60) के रूप में हुई है।

दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राजधानी की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फ्लू की मौजूदा स्थिति, अस्पतालों की तैयारियों, जांच और इलाज की सुविधाओं के साथ बीमारी को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई। यह बैठक दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी की खबरों के बीच हुई। इस साल दिल्ली में अब तक फ्लू के 1,349 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि पिछले साल सिर्फ 229 केस दर्ज किए गए थे।

मिजोरम में 5 आरोपी गिरफ्तार

मिजोरम के मामित जिला में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग असम से अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से संक्रमित 45 सुअर लेकर आए थे। सुअरों को आइजॉल ले जाया जा रहा था।

भोजशाला के पास जुमे की नमाज को लेकर तनाव

- विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ, शंख बजाकर जयघोष

धार (एजेंसी)। धार में भोजशाला से सटे खसरा नंबर 612 पर जुमे की नमाज को लेकर शुक्रवार को तनाव की स्थिति बन गई। हिंदू संगठन के सदस्य नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। शंख बजाकर जयघोष भी किया गया। वहीं, करीब 500 नमाजी निर्धारित स्थान पर नमाज अदा करने पहुंचे। खसरा नंबर 612 के मेन गेट तक नमाजियों की भीड़ रही।

प्रशासन और पुलिस ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भोजशाला के प्रवेश द्वार, बाहरी क्षेत्र और नमाज स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। करीब 1,000 जवानों का बल सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया था। इसके अलावा ड्रोन, सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए भी निगरानी की जा रही है।

भोज उत्सव समिति बोली- हर शुक्रवार करते आए हैं हनुमान चालीसा

भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे ने कहा- हम तो प्रत्येक शुक्रवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते आए हैं और करते रहेंगे। हमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का जो अधिकार हिंदू समाज को मिला है, उसी के तहत हम पूजा-पाठ कर रहे हैं। उन्होंने कहा- उससे (नमाज से) हमारा कोई लेना-देना नहीं है।

आसमान में नजर आएगा ब्लड मून, अद्भुत होगा नजारा!

अगस्त के आखिर में कई देशों में दिखेगा दुर्लभ चंद्र ग्रहण

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अगस्त का महीना खगोल वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए बेहद खास है। महीने की शुरुआत में जहां एक पूर्ण सूर्य ग्रहण आखिर में एक शानदार चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जिसे दुनिया के बड़े हिस्से में देखा जा सकेगा। इस दौरान पूर्णिमा का चांद पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिससे आसमान में वह डरावने लाल रंग में नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा का 96 प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी की छाया में होगा और केवल एक पतला हिस्सा सीधे सूरज की रोशनी में होगा। चंद्र ग्रहण तब होता है जब चांद, पृथ्वी और सूरज एक सीध में सामने आते हैं। इस दौरान चांद पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। हालांकि, चंद्र ग्रहण के दौरान चांद आसमान से गायब नहीं होता बल्कि यह गहरे लाल रंग में नजर आता है।

भारत में नहीं दिखाई देगा दुर्लभ चंद्र ग्रहण

27-28 को होने वाला गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों के साथ यूरोप और अफ्रीका के कुछ इलाकों में भी दिखाई देगा। कुछ जगहों पर काफी गहरा दिखेगा जबकि दूसरी जगहों पर इसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाई देगा। हालांकि, इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में दिन हो रहा होगा। चंद्र ग्रहण की खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण के उलट, इसे बिना किसी खास चश्मे के नंगी आंखों से देखा जा सकेगा।

सरकार महिला, युवा और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित

देहरादून के 13 गांव में खुलेगें राज्य स्तरीय विपणन केंद्र

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत चौपाल-2026 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। साथ ही 8 हजार से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता और आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। उद्घाटन सत्र में उन्होंने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गांव में प्रदेश के समस्त जनपदों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद विपणन के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की है।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे गांव प्रदेश के विकास में सहभागी ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य और परिश्रम के बल पर आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका

निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्साही युवाओं, साहसी मातृशक्ति में कुछ कर गुजरने की इच्छा और हुनर है, इसी तरह प्रदेश के स्थानीय उत्पादों में देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात कि है कि हुनर को सही दिशा मिले। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने ह्लमुख्यमंत्री उद्यमशाला योजनाह्व को आगे बढ़ाने का काम किया है। योजना के जरिए सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। साथ ही किसानों और महिलाओं की आर्थिक स्थित मजबूत हो। ह्लमुख्यमंत्री उद्यमशाला योजनाह्व इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने में मदद दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्यमिता का एक बड़ा उद्देश्य पलायन को रोकना भी है। सरकार चाहती है कि युवा रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर न हों। क्योंकि गांव मजबूत होगा तो उत्तर-खण्ड मजबूत होगा।

डोईवाला लच्छीवाला टोल पर बड़ा हादसा टला

डोईवाला। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते–होते टल गया। अचानक नियंत्रण खोने के बाद तेज रफ्तार ट्रक टोल लेन में जा घुसा। गनीमत रही कि जिस लेन में ट्रक पहुंचा, वहां उस समय कोई अन्य वाहन मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया।

जानकारी के अनुसार, ट्रक के अनियंत्रित होने का कारण ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। चालक की सूझबूझ के चलते भी कई लोगों की जान बच गई।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और टोल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बनाया।

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ट्रक के अनियंत्रित होने की वजह तकनीकी खराबी थी या चालक की लापरवाही।

एक नजर

खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटलों की चेकिंग कर शुद्धता रखने के निर्देश दिए

नई टिहरी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने जिले के अलग–अलग मोटर मार्गों पर स्थित दुकान, होटल और रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां रखे गए खाद्य पदार्थों के आठ सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। खाद्य सुरक्षा के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा टीम ने जिले के अलग–अलग स्थानों में संचालित होटल, रेस्टोरेंटों और अन्य प्रतिष्ठानों के किचन और स्टोर का निरीक्षण कर खाद्य निर्माण में प्रयुक्त दुग्ध पदार्थों के वास्तविक स्रोत, अन्य कच्चे माल की खरीद, बिल, निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त सामग्री, उत्पादों की लेबलिंग, पैकेजिंग, बैच नंबर, निर्माण तिथि और आवश्यक घोषणाओं की जांच की गई। होटल–रेस्टोरेंटों प्रयुक्त होने वाले पानी और किचन में कार्यरत कर्मचारियों के चिकित्सीय जांच संबंधी प्रपत्रों की जांच भी की गई। उपायुक्त ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान आटा, दाल, सब्जी, पोहा, चीनी, मैदा और बेकरी उत्पाद सहित कुल आठ खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजे गए हैं।

पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को ब्रांडिंग की दी जानकारी

नई टिहरी। आईटीआई में पीएम विश्वकर्मा जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। पीएम विश्वकर्मा जागरूकता कार्यशाला में एमएसएमई के निदेशक डॉ. सुनील कुमार नेवार ने पारंपरिक कारीगरों की आजीविका को सुदृढ़ करने में पीएम विश्वकर्मा योजना की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से कारीगरों को कौशल विकास, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और संस्थागत सहयोग सहित विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। बैंक कर्मियों की ओर से वित्तीय सेवाओं और औपचारिक बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंचने के बारे में बताया गया। परियोजना प्रबंधन इकाई की दिव्या राणा ने कारीगरों को व्यवसाय संवर्धन, कंटेंट निर्माण, उत्पाद डिजाइन, मार्केटिंग और ग्राहक सहभागिता में एआई के उपयोग की जानकारी दी। कारीगरों के उत्पादों की बेहतर प्रस्तुति, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं बाजार में उत्पादों की मांग बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी दी गई। कार्यशाला में 10 से अधिक पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों का आईपीपीबी डिजिटल भुगतान सेवा के लिए पंजीकरण कराया गया। बताया गया कि पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों को टिकाऊ और बाजारोन्मुखी उद्यम विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

गाली–गलौज कर मारपीट करने के आरोप से दोषमुक्त हुआ अभियुक्त

नई टिहरी। मारपीट कर गाली–गलौज करने के आरोप में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। अभियुक्त के खिलाफ कीर्तिनगर पुलिस थाने में पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।अभियोजन की ओर से बताया गया कि वादिनी मुकदमा महिला ने कीर्तिनगर पुलिस थाने में दी गई तहरीर में बताया कि उसका पति विनोद लाल लॉकडाउन से पहले आए दिन उसके और बच्चों के साथ मारपीट कर गाली–गलौज करता था। लॉकडाउन में जब वह नौकरी से घर आया तो फिर से मारपीट करनी शुरू कर दी। कई बार झगड़ा बढ़ने पर रिश्तेदारों और गांव के प्रधान ने राजीनामा कराया लेकिन उसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस कारण उसका पुत्र शाहिल मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि मार्च 2023 को उसने घर के नजदीक पेड़ पर रस्सी से लटकर अपनी जान दे दी। इससे परेशान होकर वह अपने मायके चली गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की।

500 का पिज्जा 10 हजार का पड़ा

हरिद्वार। ऑनलाइन एप के माध्यम से 10 इंच का पिज्जा ऑर्डर करने के बाद सात इंच का पिज्जा डिलीवर करना और शिकायत के बावजूद रिफंड न देना ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म और कैफे को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरिद्वार ने मामले में दोनों को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने मैसर्स बण्डल टैक्नोलॉजिस प्रा. लि. और कैफे फोस्ट फैक्टरी को संयुक्त रूप से उपभोक्ता को 10,520 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

गोलीकांड के खिलाफ कांग्रेस का जन सुरक्षा न्याय मार्च

देहरादून। राजधानी देहरादून में लगातार सामने आ रही गोलीकांड की घटनाओं और बिगड़ती कानून–व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को "जन सुरक्षा न्याय मार्च–सुरक्षित राजधानी, जवाबदेह सरकार" का आयोजन किया। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पथरी बाग चौक से लाल पुल चौक तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया।

मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी में आमजन की सुरक्षा और मजबूत कानून–व्यवस्था की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देहरादून जैसे शहर में लगातार गोलीकांड और आपराधिक घटनाओं का सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। राजधानी की जनता को डर के माहौल में रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में जीवन जीने का अधिकार है। सरकार को कानून–व्यवस्था को लेकर जवाबदेही तय करनी चाहिए

और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजधानी में कानून–व्यवस्था को लेकर जनता के बीच विश्वास मजबूत करना सरकार और पुलिस प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मांग की कि आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई के साथ–साथ अपराधियों में कानून का भय पैदा किया जाए, ताकि आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिल सके।

इस अवसर पर रीठामंडी पार्षद इताद खान, वसीम मकरानी, आदर्श सूद, कैलाश ठाकुर, मनीष धीमान, सतेंद्र, गगन चाचर, मुरसलीन, हरि शंकर, समीर कुमार, अनिल शर्मा, लक्ष्य गोयल, अभिनव, अभिषेक डोबरियाल, गौरव रावत, नितिन उनियाल, विकास यादव, उदय यादव, सोनू, कुसुम रावत, अनीता सकलानी, रुचि रौतेला, नंदिता गढ़िया, अनुराधा, बबीता, सीमा, कुसुम और विजया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मार्च में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं, युवा साथियों और स्थानीय लोगों की भी भागीदारी रही। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई।

कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के महासचिव बने भरत सिंह और मोहन सिंह

लंबगांव (टिहरी)। कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कुंदन सिंह राणा ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों का मनोनयन किया है।

कार्यकारिणी में भरत सिंह रावत और मोहन सिंह नेगी को महासचिव, भाग सिंह नेगी, मिजान सिंह असवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया है। दयाल सिंह सजवाण को जिला प्रवक्ता, पदम सिंह नेगी, अनिल कैंतुरा संगठन सचिव, प्रताप सिंह असवाल महासचिव, लक्ष्मण सिंह कलूड़ा, धनवीर सिंह बिष्ट नागेंद्र राणा सचिव और राजेश बिष्ट को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सभी नवनियुक्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित कर पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगे।

रुद्रपुर में किसानों का शक्ति प्रदर्शन

रुद्रपुर। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में शुक्रवार को किसानों का आंदोलन उस समय तेज हो गया, जब भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसान अपनी चार प्रमुख मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर गए। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने से कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर माहौल गरमा गया। किसानों ने रास्ते में लगाई गई पहली बैरिकेडिंग को पार कर लिया, जिसके बाद पुलिस–प्रशासन ने दूसरी बैरिकेडिंग के पास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी।दूसरी बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने के बजाय किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। किसानों ने दरी बिछाकर अपना आंदोलन शुरू कर दिया। प्रदर्शन स्थल पर किसानों की ओर से लंगर की भी व्यवस्था की गई, जहां आंदोलन में शामिल किसानों ने सामूहिक रूप से भोजन किया।

21 से 23 अगस्त तक तीन दिवसीय धरने का ऐलान

किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन केवल कुछ घंटों तक सीमित नहीं रहेगा। उन्होंने 21 से 23 अगस्त तक तीन दिनों तक कलेक्ट्रेट गेट के

बाहर धरना जारी रखने का ऐलान किया है। किसान नेताओं का कहना है कि जरूरत पड़ने पर प्रदर्शनकारी रात में भी मौके पर रुककर आंदोलन जारी रखेंगे।

किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई। पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही प्रदर्शनकारियों से बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं।

बिजली से लेकर जमीन के मालिकाना हक तक चार प्रमुख मांगें

भारतीय किसान यूनियन की ओर से सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखी गई हैं। किसानों की पहली मांग उत्तराखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की है। किसान नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में पहचान हासिल है, इसलिए राज्य के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। दूसरी प्रमुख मांग किसानों के ट्यूबवेल की बिजली का बिल माफ करने की है। किसानों का कहना है कि कृषि कार्यों में बिजली की लागत कम होने से उन्हें आर्थिक राहत मिल सकती है और खेती को बढ़ावा मिलेगा। तीसरी मांग बाजपुर क्षेत्र के 20 गांवों की जमीन से जुड़ी है। किसान इन गांवों के ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

तीन वारंटी गिरफ्तार, न्यायालय में किया पेश

विकासनगर। न्यायालय से जारी गैर–जमानती वारंटों की तामीली को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत विकासनगर पुलिस ने तीन वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विनय (45) और राजकुमार (57), निवासी राजावाला, पोस्ट ऑफिस अशोक आश्रम चिलियो शामिल हैं। दोनों के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित न्यायालयी मामलों में वारंट जारी थे। वहीं भट्टा पुलिस चौकी के पीछे, विकासनगर निवासी अजय सक्सैना (29) को वर्ष 2018 के धारा 379/411/356 भादवि से संबंधित मामले में जारी न्यायालयी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते हुए तीनों वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया।

जौनपुर के ग्राम प्रधानों ने खंड विकास कार्यालय में दिया धरना

थत्यूड़ (टिहरी)। जौनपुर ब्लॉक खंड विकास अधिकारी कार्यालय थत्यूड़ परिसर में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने वीबी जीरामजी योजना में श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति में आ रही समस्या को लेकर धरना दिया। ग्राम प्रधानों ने श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी बंद करने की मांग उठाई है।

जौनपुर ब्लॉक के ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि जौनपुर क्षेत्र में करीब 80 प्रतिशत गांव ऐसे हैं, जहां संचार नेटवर्क की परेशानी बनी है। इसके कारण श्रमिकों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पा रही है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति विकट होने के कारण कई गांवों में मोबाइल से बात तक नहीं हो पाती है।

ऑनलाइन उपस्थिति के कारण ग्रामीणों को योजना के तहत किए जाने कार्यों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसका असर गांव के विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। कहा कि सरकार पहले पहाड़ी क्षेत्रों में मजबूत संचार नेटवर्क की व्यवस्था करे, इसके बाद ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान शुरू करवाए। कहा कि ग्राम प्रधानों के विरोध के बाद भी यदि सरकार उनकी मांग की अनदेखी की गई तो ग्राम प्रधान आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया बंद कर पूर्व की भांति ऑफलाइन व्यवस्था को लागू करने की मांग की है। इस मौके पर ग्राम प्रधान शांति प्रसाद गौड़, सरदार सिंह पंवार, जगपाल पंवार, वासुदेव लेखवार, जीतमणी, सरस्वती रावत, रीना बिष्ट, मीनाक्षी चौहान, कुसुम रावत, मदन मोहन सेमवाल आदि मौजूद थे।

यमुना क्षेत्र में रात के डंपरों की आवाजाही पर उठे

विकासनगर। मानसून सत्र के बीच यमुना नदी क्षेत्र से जुड़े मार्गों पर देर रात भारी डंपरों की आवाजाही और क्रेशरों तक वाहनों के पहुंचने की सूचनाओं ने प्रशासनिक निगरानी और नियमों के अनुपालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी को पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए थे।

जिलाधिकारी के निर्देश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिला खान अधिकारी की ओर से जांच पूरी की गई है या नहीं? यदि जांच पूरी हो चुकी है तो उसकी रिपोर्ट में क्या तथ्य सामने आए हैं और क्या देर रात यमुना क्षेत्र से होकर क्रेशरों तक पहुंचने वाले वाहनों के संबंध में नियमों का पालन पाया गया है? वहीं, यदि जांच अभी तक लंबित है तो जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जांच पूरी होने में देरी क्यों हो रही है?

बताया जा रहा है कि मानसून के दौरान नदी

और बरसाती क्षेत्रों से जुड़े मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर सुरक्षा के साथ–साथ खनन नियमों के पालन की निगरानी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे समय में यमुना नदी क्षेत्र से जुड़े रास्तों पर रात के समय डंपरों की आवाजाही की सूचना सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मामले में यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन मार्गों से भारी वाहन गुजर रहे हैं, वहां उनके संचालन से संबंधित वैध दस्तावेज, खनन सामग्री की स्थिति, वाहन की अनुमति और अन्य निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। इन सभी बिंदुओं की स्थिति जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

जांच रिपोर्ट पर टिकी नजर

जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जिला खान अधिकारी की जांच को लेकर अब लोगों की नजर रिपोर्ट पर है। प्रशासन की ओर से जांच में क्या–क्या बिंदु शामिल किए गए हैं और मौके पर क्या स्थिति पाई गई, यह रिपोर्ट सार्वजनिक होने या संबंधित अधिकारियों की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा।

मालदेवता की सास–बहू ने राखी कारोबार से रची सफलता की कहानी

देहरादून। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आते ही बाजार रंग–बिरंगी राखियों से सजने लगे हैं। इसी बीच देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने हुनर को कारोबार में बदलकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। रायपुर विकासखंड के मालदेवता क्षेत्र की सास–बहू लीला रावत और अलका रावत की जोड़ी भी इसी बदलाव की प्रेरक कहानी बनकर सामने आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ी लीला और अलका हाथ से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। इस वर्ष दोनों ने दो हजार से अधिक राखियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें अब तक करीब 1500 राखियां तैयार हो चुकी हैं।

1200 राखियों से कमाया 25 हजार रुपये का मुनाफा

लीला और अलका ने बताया कि पिछले वर्ष प्रशासन के सहयोग से उन्हें राखियों की बिक्री के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ था। दोनों ने करीब 1200 हैंडमेड

राखियां तैयार कर बाजार में बेचीं, जिससे उन्हें लगभग 25 हजार रुपये का मुनाफा हुआ। पिछले वर्ष मिले अच्छे बाजार और ग्राहकों की प्रतिक्रिया से उत्साहित होकर दोनों ने इस वर्ष राखी कारोबार को और बड़े स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया। अब राखियां उनके लिए केवल रक्षाबंधन से जुड़ा मौसमी उत्पाद नहीं हैं, बल्कि परिवार की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने का जरिया बन चुकी हैं।

प्राइवेट नौकरी छोड़ी, सास के साथ शुरू किया स्वरोजगार

अलका रावत ने पिछले वर्ष अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़कर अपनी सास लीला रावत के साथ स्वरोजगार शुरू करने का फैसला लिया। दोनों ने मालदेवता क्षेत्र में ह्वविनी वंडर्स क्रिएशनह्व नाम से दुकान शुरू की। एनआरएलएम के सहयोग से संचालित इस कारोबार में राखियों के अलावा अन्य हस्तनिर्मित और स्थानीय उत्पाद भी तैयार एवं बिक्री किए जाते हैं। अलका के अनुसार स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आय के नए अवसर मिले और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आर्थिक रूप से मजबूत बनने का रास्ता खुला।

इंस्टाग्राम से भी मिल रहे राखियों के ऑर्डर

मालदेवता की इन महिलाओं का कारोबार अब स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रह गया है। ह्वविनी वंडर्स क्रिएशनह्व के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उन्हें राखियों के ऑर्डर मिल रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बाद महिलाएं स्वयं राखियां तैयार करने के साथ उनकी पैकेजिंग और डिलीवरी की व्यवस्था करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनके ग्रामीण कारोबार को स्थानीय बाजार से बाहर नए ग्राहकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है।

क्रेशिया से रुद्राक्ष तक, अलग–अलग डिजाइन की राखियां

महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही राखियों में पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। ऊन, क्रेशिया, मौली के धागे और रिबन समेत विभिन्न सामग्रियों का इस्तेमाल कर आकर्षक राखियां बनाई जा रही हैं। भैया दूज, महाकाल, रुद्राक्ष और नजरबट्टू जैसे अलग–अलग डिजाइन ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।

दुकानें हटाने से पहले वैकल्पिक स्थान देने की मांग, व्यापारियों का धरना जारी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित दुकानों को हटाने की कार्रवाई से पहले वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग को लेकर व्यापारियों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। एक सूत्रीय मांग को लेकर व्यापारी पिछले तीन दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि अब तक किसी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि मांग पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवीण भाटिया के नेतृत्व में व्यापारियों ने शुक्रवार को शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। व्यापारियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जिस स्थान पर उनकी दुकानें संचालित हो रही हैं, वह उन्हें दशकों पहले उपलब्ध कराई गई थी। इन छोटी दुकानों से ही कई परिवारों की आजीविका चल रही है। व्यापारियों ने कहा कि अचानक दुकानें खाली करने का फरमान जारी होने से उनके सामने रोजी-रोटी

कोटद्वार स्टेशन में धरने पर बैठे व्यापारी

का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की कि दुकानों को हटाने से पहले सभी प्रभावित व्यापारियों के लिए अन्यत्र स्थान की व्यवस्था की जाए, ताकि उनका रोजगार प्रभावित न हो। धरने पर बैठे व्यापारियों ने कहा कि वे अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यदि जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उन्हें आंदोलन तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कोटद्वार में बाजार और यातायात बंद कराने की चेतावनी भी दी। धरने में प्रदीप कुमार, संदीप डोबरियाल, सोनू सैनी, जगन लाल, राकेश भाटिया, हरदीप सिंह, रजनीश, भूपेश चंद्र, मुकेश कुमार वर्मा, अर्जुन सिंह बिष्ट, रतन लाल, पुनीत वर्मा और मंगत राम सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे।

प्रो. सिन्हा मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : एचएनबी गढ़वाल विवि में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सितंबर में प्रस्तावित छात्रसंघ चुनाव को लेकर विवि ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डॉ. बीजीआर परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रो. पीयूष सिन्हा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया है। डॉ. बीजीआर परिसर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बैठक आयोजित हुई। चुनाव को शांतिपूर्व व निष्पक्ष कराए जाने की रणनीतियों पर चर्चा हुई। साथ ही परिसर निदेशक प्रो. यूसी गैरोला ने चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारियों को तैनात कर दिया है।

बताया कि इस बार भी वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. पीयूष सिन्हा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जबकि डॉ. विपुल सिंह और डॉ. विक्रम सिंह नेगी को सहायक निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को विवि के लागू नियमों और लिंगदोह समिति के दिशा निर्देशों के तहत चुनाव की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

नर्सरी का ताला तोड़ 50 हजार उड़ाए, दो युवक गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस की हिरासत में आरोपी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : क्षेत्र की एक नर्सरी के गल्ले का ताला तोड़कर 50 हजार रुपये की नकदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी की गई धनराशि भी बरामद कर ली है।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार को संगीता चौधरी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि रात के समय दो अज्ञात युवक उनकी नर्सरी में घुसे और गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखे 50 हजार रुपये चोरी कर फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू करते हुए घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि मामले में मवाकोट निवासी देवांग सकलानी और घमंडपुर निवासी दीपक को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के कब्जे से चोरी की गई 50 हजार रुपये की नकदी बरामद कर ली गई है। मामले में पुलिस की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

शिक्षक बच्चों को सुरक्षित वातारण और सही दिशा दें

श्रीनगर गढ़वाल : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) चड़ीगांव में तीन दिवसीय बालसखा कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें 15 विकासखंडों के 38 शिक्षकों ने विद्यार्थियों के समग्र विकास पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को बालकों की क्षमताओं और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित मार्गदर्शन हेतु सक्षम बनाना था। समापन सत्र में डॉ. शिवकुमार भारद्वाज ने राष्ट्रीय कार्यक्रम ह्यपरखह्न के तहत पौड़ी की रिपोर्ट साझा की।

शैक्षिक रैंकिंग सुधारने के लिए उपचारात्मक शिक्षण और प्रभावी रणनीतियों पर जोर दिया गया। प्राचार्य डॉ. स्वराज सिंह तोमर ने कहा कि शिक्षक का दायित्व ह्यबालसखाह्न बनकर बच्चों को सुरक्षित वातावरण और सही दिशा देना है। समन्वयक डॉ. जगमोहन पुंडीर ने शिक्षकों से कार्यशाला में सीखी गतिविधियों को विद्यालयों में लागू करने का आह्वान किया। संचालन विनय किमोठी ने किया। (एजेंसी)

आईटीआई खोलने की मांग, तकनीकी शिक्षा मंत्री को भेजा पत्र

कीर्तिनगर : विकासखंड कीर्तिनगर के हिंसरियाखाल क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोलने की मांग उठी है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और निवासियों ने तकनीकी शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया है।

पत्र में कहा गया है कि हिंसरियाखाल के आसपास कोई सरकारी आईटीआई नहीं है। इससे गरीब और सामान्य परिवारों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। निजी संस्थानों की अधिक फीस के कारण कई छात्र प्रवेश नहीं ले पाते हैं। स्थानीय युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर जैसे रोजगारपरक ट्रेडों में प्रशिक्षण मिलेगा। इससे वे तकनीकी रूप से दक्ष होकर आत्मनिर्भर बनेंगे। उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

पत्र भेजने वालों में ग्राम प्रधान सौडू निर्मला देवी, ग्राम प्रधान गौंली अर्जुन, ग्राम प्रधान बरसोली अनीता देवी, ग्राम प्रधान नौली शांति देवी, ग्राम प्रधान डडुवा बीना, ग्राम प्रधान भंडाली सुरेश, ग्राम प्रधान संजना देवी आदि शामिल हैं। (एजेंसी)

पिता-पुत्र की मौत पर संदेह, पीएम रिपोर्ट का इंतजार

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : थलीसैंण थाना क्षेत्र के मरोड़ा गांव में पिता-पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस को चौबीस घंटे बाद भी तहरीर नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। तहरीर मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।

पुलिस के अनुसार 19 अगस्त की शाम मरोड़ा निवासी बिगारी सिंह (53) और उनके पिता बख्तावर सिंह (85) ने एक साथ शराब पी थी। इसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई थी। परिजन उन्हें सीएचसी थलीसैंण ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया था।

पुलिस को प्रारंभिक जानकारी में यह पता चला कि पिता-पुत्र के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर अक्सर कहासुनी होती थी। सीओ सदर तपेश कुमार चंद ने बताया कि मामले में अभी तक परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांच के आधार पर मामले की स्थिति स्पष्ट होगी। तहरीर मिलने पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करेगी।

एनएचबी ने उत्तराखण्ड के लिए तैयार की अलग से योजना

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की ओर से अब प्रदेश में बागवानी से जुड़े विभिन्न प्रोजेक्टों को नए प्राविधानों के तहत शुरू किया जा सकेगा। एनएचबी ने उत्तराखंड को मैदानी राज्यों से पृथक कर नए प्राविधान तैयार किए हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने पौड़ी में पत्रकार वार्ता कर बोर्ड की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दीं। कहा कि बीते दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें उत्तराखंड में बागवानी की संभावनाओं और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश का पक्ष रखा। जुयाल ने बताया कि अभी तक एनएचबी की ओर से प्रदेश को मैदानी राज्यों के साथ योजनाओं में शामिल किया जाता था जिससे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बागवानी किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता था। जुयाल के प्रस्ताव पर बोर्ड ने राज्य के लिए अलग से योजना तैयार की है। नए बदलावों में अब एक हेक्टेयर जमीन पर भी बड़े प्रोजेक्टों पर एनएचबी से अनुदान आदि कार्य किए जा सकेंगे।

28 और 29 अगस्त को होंगी जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं

ऋषिकेश। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर टिहरी खेल विभाग की ओर से 28 और 29 अगस्त को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी टिहरी दीपक रावत ने बताया कि प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए खेल विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। अलग-अलग खेलों के लिए नई टिहरी, नरेंद्रनगर और मुनि की रेती में आयोजन स्थल तय किए गए हैं। ओपन बालक वर्ग शॉटपुट प्रतियोगिता बौराड़ी स्टेडियम,नई टिहरी व ओपन बालक वर्ग बैडमिंटन के सिंगल्स और डबल्स मुकाबले जिला खेल कार्यालय नरेंद्रनगर स्थित बैडमिंटन हॉल में आयोजित किए जाएंगे।

स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए विद्यार्थी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : प्रखंड एकेश्वर के अंतर्गत पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं टीकाकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों को एचपीवी टीकाकरण, मासिक धर्म स्वच्छता, हाथ धोने के सही तरीके तथा बरसात के मौसम में दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यशाला का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह नेगी ने किया। उन्होंने एचपीवी वैक्सीन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह टीका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर सहित एचपीवी से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक है। आयुष्मान केंद्र धरासू की एएनएम ज्योति ने छात्राओं को एचपीवी टीकाकरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 9 से 15 वर्ष की आयु में टीकाकरण अधिक प्रभावी माना जाता है। इस आयु वर्ग

प्रखंड एकेश्वर के पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में विद्यार्थियों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी देते शिक्षक व स्वास्थ्यकर्मी।

में दो खुराक, जबकि 15 से 26 वर्ष की आयु में तीन खुराक दिए जाने की जानकारी उन्होंने दी। आशा सुपरवाइजर पूर्णिमा सुंदरियाल ने मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक एवं सामान्य जैविक प्रक्रिया है। इस दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने, सेनेटरी नैपकिन को नियमित रूप से बदलने और संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई। वहीं, ग्राम पंचायत धरासू की आशा कार्यकर्ता मंजू नेगी ने बरसात के मौसम में दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैजा, टाइफाइड, पेचिश, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियां दूषित पानी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों के कारण फैल सकती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से साफ पानी का सेवन करने और व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों को हाथ धोने के सही तरीके भी बताए गए और स्वच्छता को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया।

नए एवं रचनात्मक विचारों के साथ शोध करने पर दिया जोर

श्रीनगर गढ़वाल : हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी) के तत्वावधान में विश्व उद्यमिता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रो. डीएस नेगी ने विद्यार्थियों को नए विचारों को विकसित कर उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए प्रेरित किया। प्रो. एससी सती ने विद्यार्थियों को नए एवं रचनात्मक विचारों के साथ शोध कार्य करने पर जोर दिया। कहा कि नवाचार आधारित शोध समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम संयोजक डॉ. भास्करन ने विश्व उद्यमिता दिवस के महत्व तथा नवाचार और उद्यमिता की वर्तमान समय में उपयोगिता की जानकारी दी। डॉ. विजयकांत एवं डॉ. सुरेंद्र पुरी ने शोधार्थियों को अपने शोध कार्य में नवीन दृष्टिकोण अपनाने तथा नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉ. रोहित मगर ने सभी का आभार व्यक्त किया। (एजेंसी)

संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करें कार्यकर्ता : सुरेंद्र सिंह नेगी

जयन्त प्रतिनिधि।कोटद्वार : पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन की वास्तविक ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए काम करना होगा। आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अभी से जनता के बीच सक्रिय होकर कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाना चाहिए। नेगी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान के लिए संघर्ष करना प्रत्येक कार्यकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। बूथ स्तर पर मजबूत संगठन, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनता से सीधा संवाद ही चुनावी सफलता का आधार बनेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार कर संगठन हित में एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र, जनहित और सामाजिक न्याय की आवाज उठाती रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाते हुए पार्टी की विचारधारा को प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का काम करना होगा। कार्यक्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मीना बछुवाण, पूर्व ब्लॉक प्रमुख गीता नेगी, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीन रावत, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. चंद्रमोहन खर्कवाल, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह बिष्ट, रुचि कैन्तुरा, बलबीर सिंह रावत, विजय रावत, अनिल गुसाईं, प्रीति देवी, उदय नेगी, पूनम मेहरा, हेम चंद्र पंवार, कुलवंत पुंडीर, अनिल नेगी, मनोज रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मालन नदी का वैकल्पिक मार्ग बदहाल

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : मालन नदी में बने वैकल्पिक मार्ग के लगातार हो रहे कटाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने चिंता जताई है। यूकेडी ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार किया गया यह वैकल्पिक मार्ग अब नदी के तेज बहाव की चपेट में आने की स्थिति में है। मार्ग का बड़ा हिस्सा नदी में बह चुका है और मौके पर अब केवल ह्यूम पाइप का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा हिस्सा भी मिट्टी में दब गया है।

यूकेडी के केंद्रीय प्रचार सचिव रविंद्र सौंद ने कहा कि करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नदी की भेंट चढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को कई बार प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन मार्ग को बचाने या उसके पुनर्निर्माण के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि वैकल्पिक मार्ग का उद्देश्य भारी मालवाहक वाहनों को मालिनी नदी के मुख्य पुल से गुजरने की आवश्यकता कम करना था। इससे जहां क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिलती, वहीं मुख्य पुल पर वाहनों का

आयोजित बैठक में भाग लेते उक्रांद कार्यकर्ता

दबाव भी कम होता। उन्होंने प्रशासन से मार्ग को बचाने के लिए तत्काल सुरक्षा कार्य कराने और आवश्यक होने पर इसके पुनर्निर्माण की मांग की। यूकेडी महानगर अध्यक्ष भरत मोहन काला ने मालिनी नदी के मुख्य पुल की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पुल पर जगह-जगह गड्ढे बने हुए हैं। भारी व्यावसायिक वाहनों की लगातार आवाजाही, ब्लैकटॉपिंग का अभाव और निर्माण कार्य की गुणवत्ता जैसे कारण पुल की स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए समय रहते ठोस कदम उठाना जरूरी है। आपदा प्रबंधन केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संवेदनशील स्थानों पर इसका असर धरातल पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मालन नदी के वैकल्पिक मार्ग और मुख्य पुल की स्थिति का तत्काल निरीक्षण कर आवश्यक कार्य कराने की मांग की।

मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के लिए विद्यार्थियों का चयन

जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल एकेश्वर के आठ छात्र-छात्राओं का ह्यमुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्तिह्न योजना के लिए चयन हुआ है। छात्रों के चयन से विद्यालय में खुशी की लहर है।

जिला क्रीड़ा विभाग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में स्कूल के इन होनहार छात्रों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। चयनित छात्रों को अब सरकार द्वारा 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने खेल अभ्यास को और बेहतर तरीके से जारी रख सकेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य बलदेव सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के लिए तेजस्व शाह, लावर्णया बौद्ध, सानवी पंवार, दीपिका, अरूण रावत, समृद्धि बडोला, अंश रावत, उदित रावत का चयन हुआ है। प्रधानाचार्य ने सभी चयनित छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल के बच्चे खेल और शिक्षा दोनों में आगे बढ़कर राज्य का नाम रोशन करेंगे।

भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुआ रैडा-कमलखेत संपर्क मार्ग

जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम रैडा से राजकीय इंटर कॉलेज कमलखेत को जोड़ने वाला मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से स्कूली छात्र-छात्राओं और स्थानीय ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है। क्षेत्र में कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना घटने का अंदेशा बना हुआ है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह संपर्क मार्ग पिछले साल 2025 में भी आपदा के दौरान टूट गया था। उस समय आपदा प्रबंधन विभाग को तुरंत सूचित करने के बाद भी शासन-प्रशासन के स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। थक-हारकर ग्रामीणों ने अपने स्तर से चंदा और श्रमदान कर इस मार्ग को आवाजाही लायक बनाया था, लेकिन हाल ही में हुई भारी बारिश ने इसे एक बार फिर पूरी तरह से बहा दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी सतपुली को ज्ञापन सौंपा और मार्ग के नवनिर्माण की मांग की। ग्रामीणों की शिकायत पर मामले का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी को स्थलीय जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके तुरंत बाद नायब तहसीलदार सतपुली ने संबंधित क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक कानूनगो और राजस्व उपनिरीक्षक को इस प्रकरण की तत्काल जांच कर समय से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द ही क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया, तो क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे बच्चों का भविष्य और ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह संकट में पड़ जाएगा।

जेंटा–कोटी में संचार सुविधा नहीं

कर्णप्रयाग। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जन जागृति यात्रा शुक्रवार को ब्लॉक के ग्राम पंचायत जेंटा–कोटी पहुंची। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उक्रांद युवा प्रकोष्ट के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी को क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं बताईं।

उन्होंने कहा कि विगत चार वर्ष पूर्व क्षेत्र की आठ ग्राम पंचायतों को दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत घतोड़ा में लगाया गया मोबाइल टावर अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में ग्रामीणों को संचार सेवा के लिए भटकना पड़ता है। आशीष नेगी और डॉ. मदन मोहन नवानी ने ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आंदोलन की चेतावनी दी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-पौड़ी।

पत्रांकः 959 /दो-लेखा/शुद्धि पत्र/2026-27 दिनांकः 21/08/2026

निविदा निरस्तीकरण सूचना

इस कार्यालय की निविदा सूचना संख्या-899/दो-लेखा/निविदा सूचना-02/2026-27 दिनांक, 12-08-2026 के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों की निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसके अन्तर्गत क्रम सं0 03 एवं क्रम सं0 04 पर अंकित निर्माण कार्यो की निविदायें अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दी जाती है एवं शेष कार्यों की निविदायें दिनांक 31-08-2026 तक विक्रय की जायेंगी एवं दिनांक 01-09-2026 को खोली जायेंगी। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
निविदा पृथक से पुनः आमंत्रित की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड पौड़ी।
(0391/59)

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

विभाग	Electrical (TRD)	Electrical (TRD)
टेंडर नं.	T-08-TRD-MB-26-27	T-09-TRD-MB-26-27
कार्य का नाम	मुरादाबाद डिवीजन में ADSTE/HRI के अंतर्गत TUV >20000 वाले एल.सी. गेटों के इंटरलॉकिंग के संबंध में टीआरडी, कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।	मुरादाबाद डिवीजन में ADSTE/MB के अंतर्गत TUV >20000 वाले एल.सी. गेटों के इंटरलॉकिंग के संबंध में टीआरडी, कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	11.09.2026, 15:00 Hrs	11.09.2026, 15:00 Hrs
कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	रु. 91,54,735.82/- (Including GST@18%)	रु. 79,38,337.79/- (Including GST@18%)
बिड सिक्यूरिटी राशि (रु.)	रु. 1,83,100/-	रु. 1,58,800/-
निविदा प्रपत्र मूल्य (रु.)	NIL	NIL
ऑफर की वैधता (दिन)	60 days	60 days
कार्य पूरा करने की अवधि	06 Months	06 Months
वेबसाइट एवं कार्यालय का पता	www.ireps.gov.in Divisional Railway Manager's Office, Northern Railway, Moradabad.	www.ireps.gov.in Divisional Railway Manager's Office, Northern Railway, Moradabad.

सं.: Elect/TRD/MB/2026-27/TN-11 दिनांक: 20.08.2026 2914/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

संपादकीय

रेलवे के बदहाल स्टेशन

रिपोर्ट इस सोच चुनौती देती है कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण बुनियादी यात्री सेवाओं की गारंटी कर देता है। जहां स्टेशनों को फिर से बनाया गया, उनमें से भी कई जगहों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा वैसे तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब उनकी बदहाली की विस्तृत तस्वीर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी सामने रखी है। गैर–उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं एवं स्वच्छता के हाल पर केंद्रित यह रिपोर्ट सभी 16 रेलवे जोनों के 512 ऐसे स्टेशनों के ऑडिट पर आधारित है। सीएजी ने स्टेशनों का चयन यात्रियों की आवाजाही और वहां से होने वाली कमाई को ध्यान में रखते हुए किया। उसने रेलवे डेटा, यात्री शिकायतों, यात्री प्रतिक्रियाओं, और रेलवे अधिकारियों के साथ मिल कर किए गए निरीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष है कि 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशनों पर एक या अधिक न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की कमी है। और समस्या केवल छोटे स्टेशनों पर ही नहीं, बल्कि बड़े, उच्च–राजस्व और अधिक यात्री आवाजाही वाले स्टेशनों पर भी उसी तरह मौजूद है।

समस्या हैः सुविधाओं का ना होना और जो सुविधाएं मौजूद हैं, उनकी नाकाफी क्षमता तथा उनका रखरखाव ठीक ना होना। रिपोर्ट के मुताबिक 188 स्टेशनों पर पेय जल के पर्याप्त नल उपलब्ध नहीं थे, जो रेल मंत्रालय के इस दावे का खंडन करता है कि ऐसी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। रिपोर्ट इस सोच चुनौती देती है कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण खुद ही बुनियादी यात्री सेवाओं की गारंटी कर देता है। यहां तक कि जहां स्टेशनों को फिर से बनाया गया है और जिन्हें बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेशन समझा जाता है, उनमें से भी कई जगहों पर यात्रियों को पानी, पंखे, बैठने की जगह, शौचालय, और स्वच्छता की कमी आदि का सामना करना पड़ रहा है।

चिंतन-मनन

चैन से सोना है तो सोने को कहें ना

सोने की चमक सभी को आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण लोग अधिक से अधिक सोना खरीदने चाहते हैं। यह चाहत तब और भी बढ़ जाती है जब सोने की कीमत में अचानक थोड़ी गिरावट आती है। लोग इस मौका का लाभ उठाना चाहते हैं। आज कल बाजार में यही स्थिति है क्योंकि सोने की कीमत कमी आयी है। आइए जानें सोने के बारे में हमारे शास्त्रों क्या कहा गया है। ज्यादातर पौराणिक ग्रंथों में इस बात को कई तरह से कहा गया है कि सोने की खरीदारी से जितनी खुशी नहीं होती है उससे अधिक चिंता बढ़ जाती है। हमेशा यह चिंता सताती है कि सोना चोरी न हो जाए। इसे कैसा संभालकर रखें। पड़ोसी की नजर सोने के गहनों पर नहीं जाए, क्योंकि नजर लग जाएगी।यह भी कहा जाता है कि किसी अवसर पर सोने के गहने पहन लें तो हमेशा इसी पर ध्यान रहता है कि कहीं गिर न जाए, कोई खींच न ले। इस चिंता के कारण उत्सव का पूरा आनंद भी नहीं उठा पाते हैं। सोना सिर्फ आपको चिंतित ही नहीं करता है बल्कि आपकी सोच और व्यवहार को भी प्रभावित करता है। इससे अभिमान भी जन्म लेता है। यही कारण है कि रहीम ने लिखा है कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय। वा खाये बौराय नर, वा पाये बौराय।। इस दोहे में रहीम ने दो बार कनक शब्द का प्रयोग किया है। एक कनक धतूरे के लिए और दूसरा सोना के लिए। रहीम ने कहा है कि सोने का नशा धतूरे भी ज्यादा होता है। धतूरा खाने के बाद आदमी बौरा जाता है लेकिन सोने का नशा इतना तेज होता है कि इसे प्राप्त कर लेने मात्र से इंसान बौरा जाता है। पुराणों में कथा है कि कलियुग का प्रवेश भी सोने के माध्यम से हुआ था। कलियुग सोने में निवास करता है इसलिए सोने के कारण विवाद और रिश्तों में दूरियां तक आ जाती है। साधु पुरूष कहते हैं कि सोना चिंता का बड़ा कारण है। जब आप इसे पाने की सोचने लगते

स्कूलों के दरवाजे बंद, सवालों से क्यों डर रहीं हैं सरकारें?

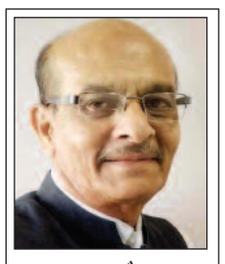

सनत जैन

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) कार्यकताओं के साथ ग्रामीणों की झड़प और मारपीट की घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीजेपी का आरोप है, इस विरोध के पीछे भाजपा समर्थक थे। उपलब्ध रिपोर्ट में भाजपा ने दावा किया है, ग्रामीणों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकताओं का विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट कर उनके वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है। मुद्दा केवल यह नहीं है, जयपुर में किसने किसे पीटा। असली प्रश्न यह है, सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति देखने, उसकी तस्वीर लेने और उसे जनता के सामने रखने से किसे डर लग रहा है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश तथा फोटो-वीडियोग्राफी के लिए प्रधानाचार्य की अनुमति अनिवार्य करने का आदेश क्यों सामने आया है? छात्रों से बातचीत करने पर क्यों रोक लगाई जा रही है? आदेश पर सरकार का तर्क बच्चों की सुरक्षा, निजता और विद्यालय में अनावश्यक व्यवधान को रोकने की बात कही जा रही है। यह तर्क पूरी तरह से सही नहीं है। यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब जेन-अल्फा के स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी मांग को लेकर कई राज्यों के कई स्थानों पर सड़क पर उतरे हैं। जब सीजेपी एवं अन्य राजनीतिक दल सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर अभियान चला रहे हैं, तब स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और सच को छुपाने को लेकर सवाल उठते हैं।

उत्तर प्रदेश में भी बिना अनुमति सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों और यूट्यूबर्स के प्रवेश पर रोक की खबर है। वहां भी प्रशासन का तर्क सुरक्षा और पढ़ाई में व्यवधान बताया गया है। यह कहना कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकारें अपनी कमियां छिपाना चाहती हैं। पारदर्शिता और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, यह सवाल जरूर महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े छात्र संगठनों की सक्रियता को इसी व्यापक राजनीति से जोड़ा जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा भाजपा से जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन लंबे समय से विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर-के वहां हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन पर इस तरीके की कोई रोक-टोक नहीं है। यदि कोई संगठन स्कूल-कॉलेजों की समसस्यों को देखकर और सुनकर समाधान के लिए प्रशासन और सरकार के सामने लाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में उसका स्वागत होना चाहिए। यही अधिकार विपक्षी दलों और स्वतंत्र सामाजिक संगठनों को भी मिलना चाहिए। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। शिक्षा संस्थान किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं हैं। वे जनता के पैसे से चलते हैं। वहां पढ़ने वाले बच्चे समाज के भविष्य हैं। स्कूल की टूटी छत, जर्जर भवन, शिक्षक की कमी, शौचालय, पेयजल, प्रयोगशाला या पाठ्यपुस्तकों की कमी की किसी भी समस्या को उजागर करने वाला व्यक्ति राजनीतिक विरोधी हो सकता है। कम उम्र के छात्रों की समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। ऐसी स्थिति में कम उम्र के छात्रों के अधिकार को कैसे छीना जा सकता है।

जयपुर की घटना इसलिए गंभीर है, क्योंकि सीजेपी शिक्षा एवं परीक्षा संबंधी मुहिम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। राजस्थान में प्रशासन, पुलिस और भाजपा कार्यकताओं से टकराव की खबरें सामने आना चिंता का कारण है। कुछ दिन पहले अलवर में जर्जर स्कूल को लेकर सीजेपी अभियान के बाद सरकार द्वारा मांगें स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट आई थी। इसका अर्थ यह है कि दबाव बनाने वाली सक्रियता से व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है। राजनीति का सबसे खतरनाक रूप तब सामने आता है, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जंग मुद्दों पर नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मैदान से हटाने के लिए होने लगे। भाजपा कार्यकताओं ने किसी संगठन के कार्यकताओं पर हमला किया है? तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। यदि सीजेपी के कार्यकताओं ने बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश किया या स्थानीय लोगों को आपत्ति थी, उसके लिए कानून के तहत शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया होनी चाहिए। भीड़ को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सोशल मीडिया पर चल रहे जेन जेड और जेन अल्फा से जुड़े आंदोलनों को लेकर भी राजनीतिक दलों में नई रणनीतियां बनना शुरू कर दी हैं। छात्र एवं युवा अब आश्वासन राजनीतिक भाषण नहीं सुनता है। वह अपनी समस्याओं का समाधान निश्चित समय सीमा पर चाहता है। वह सवाल का जवाब भी तुरंत चाहता है। आने वाले समय में शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था, फीस, डिजिटल अधिकार और सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता बड़े राजनीतिक मुद्दे बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा और संघ परिवार यदि युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में सक्रियता बढ़ाते हैं। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विपक्षी दल भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष को समान अधिकार प्राप्त हैं। मुकाबला होना चाहिए,विचारों मे हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सरकार के लिए सबसे अच्छा रास्ता स्कूलों के दरवाजे बंद करना नहीं, स्कूलों की समस्याओं को जवाबदेही के साथ सुलझाना और पारदर्शी बनाना है। कोई भी कैमरा वहां की व्यवस्था की सच्चाई को दिखाएगा, तो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जवाबदेह होंगे। सरकार को इसमें शर्मिंदा होने के स्थान पर, जिन अधिकारियों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि व्यवस्थाओं में सुधार हो। बाहरी लोगों के प्रवेश के लिए नियम बनाना उचित हो सकता है, मगर स्वतंत्र निरीक्षण, पत्रकारिता और जनप्रतिनिधियों की निगरानी के लिए स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। जयपुर में जो घटना हुई है, उसकी निष्पक्ष जांच से सच सामने आना चाहिए। इसमें भाजपा कार्यकताओं की भूमिका है, तो उन पर कार्रवाई हो, यदि किसी पक्ष ने कानून तोड़ा है, उसके खिलाफ समान कार्रवाई हो। लोकतंत्र में सत्ता की असली ताकत विरोधी आवाज को दबाने में नहीं, बल्कि विरोधी आवाज सुनकर व्यवस्था को बेहतर बनाने में है। सरकारी स्कूलों के दरवाजे बच्चों के लिए खुले रहने चाहिए। उनकी समस्याओं पर सवाल पूछने वालों के लिए भी लोकतांत्रिक रास्ते भी खुले रहने चाहिए। सवाल स्कूल का नहीं छात्रों के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। यदि 16 साल से कम उम्र के छात्र सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यह सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण है। वर्तमान का बच्चा अपनी जरूरत के लिए इसी तरह का प्रदर्शन अपने घर पर भी करता है और अब वह स्कूल में उसकी जो जरूरत है उन मांगों को लेकर जब सड़कों पर उतर रहा है तो इस मामले को दबाया नहीं जा सकता है। बच्चे तो बच्चे हैं, जिद करेंगे, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। उनका प्रदर्शन आक्रामक ही होता जाएगा।

सड़क पर पैदल चलना भी मौलिक अधिकार, फिर फुटपाथ क्यों बेहाल?

सुनील कुमार महला

सड़क पर पैदल चलना मौलिक अधिकार है, लेकिन आज भारत के कई शहरों में पैदल चलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। दरअसल, आज भी बहुत से शहरों में फुटपाथ या तो बने ही नहीं हैं, या उन पर अतिक्रमण, पार्किंग और निर्माण सामग्री के कारण लोगों के चलने की जगह नहीं बचती। ऐसे में यहां पर प्रश्न यह उठता है कि जब किसी व्यक्ति के पास सड़क पर सुरक्षित रूप से पैदल चलने की जगह ही नहीं है, तो उसे वास्तव में आवागमन की आजादी कैसे मिल सकती है?

उक्त संदर्भ में यहां पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि कुछ समय पहले ही यानी कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा है कि सुरक्षित और निर्धारित पैदल मार्ग पर चलना भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत आवागमन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वास्तव में, यह मामला उस दुखद घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें पांच साल के एक बच्चे की सड़क पर टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वहां न फुटपाथ था और न ही सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था। कहना गलत नहीं होगा कि आज कई भारतीय शहरों में फुटपाथ पर अतिक्रमण, टूटे या गायब फुटपाथ, सड़क पार करने के लिए अपर्याप्त क्रॉसिंग, तेज रफ्तार वाहन और यातायात नियमों का उल्लंघन पैदल यात्रियों के लिए जोखिम बढ़ाते हैं और हमारे देश में पैदल यात्रियों की सुरक्षा अभी भी एक गंभीर चुनौती है। आंकड़ों की बात करें तो सरकारी भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में 35,221 पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हुई, जो कुल सड़क दुर्घटना मौतों का 20.4% थी।सच तो यह है कि आज पर्याप्त पैदल यात्री बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है?। यहां पाठकों को बताता चलूं कि फुटपाथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यतः राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के दायरे में आता है, इसलिए सरकारों और संबंधित निकायों को इन पर ध्यान देना चाहिए। यहां पाठकों को बताता चलूं कि वैसे विश्व में सड़क की गुणवत्ता, फुटपाथ, पैदल पार-पथ, ट्रैफिक नियंत्रण और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के मामलों में नीदरलैंड को दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरणों में गिना जाता है। सच तो यह है कि नींदरलैंड पैदल चलने के लिए दुनिया में एक अग्रणी देश है, जहां पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए अलग एवं सुरक्षित मार्ग, कम गति वाले क्षेत्र और बेहतर सड़क डिजाइन उपलब्ध हैं। नींदरलैंड के बाद डेनमार्क विशेषकर कोपेनहेगन में पैदल यात्रियों के लिए सुव्यवस्थित फुटपाथ, क्रॉसिंग और ट्रैफिक-शांत क्षेत्र हैं। वहीं पर स्वीडन विश्व में कम पैदल मृत्यु दर और मजबूत सड़क-सुरक्षा व्यवस्था के कारण अग्रणी देशों में शामिल है।नॉर्वे(यूरोप में) तथा फिनलैंड भी पैदल मार्गों और सड़क पार करने की सुरक्षित व्यवस्था के मामले में विश्व में अहम और महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

हाल फिलहाल, यहां यह कहना चाहूंगा कि 19 जून 2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क पर पैदल चलने के संदर्भ में जो फैसला दिया है,इस फैसले का सीधा सा संदेश यही है कि सरकार और स्थानीय निकायों की यह जिम्मेदारी है कि ये लोगों को सुरक्षित फुटपाथ और सड़क पार करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराएं। वास्तव में,सच तो यह है कि नगर निगम, नगरपालिका, शहरी विकास प्राधिकरण और पंचायतों को आगे आकर इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से काम करना होगा।बहरहाल, यदि हम यहां पर आंकड़ों की बात करें तो, आंकड़े हमारी चिंताएं बढ़ाते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में लगभग 20 प्रतिशत से अधिक लोग पैदल यात्री होते हैं। कई शहरों में फुटपाथ टूटे हुए, संकरे, असुरक्षित या लगातार बाधित पाए गए हैं। यानी समस्या केवल फुटपाथ बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, चौड़ा, समतल और सभी के लिए सुगम बनाने की है। वास्तव

में,इसके लिए यह बहुत ही जरूरी है कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग न हो, वहां पर पर्याप्त रोशनी हो, सड़क पार करने के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग बने और दिव्यांगजनों के लिए रैंप तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। सड़क की खुदाई या निर्माण कार्य के दौरान भी पैदल यात्रियों के रास्ते को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए।

निष्कर्षतः यह बात कही जा सकती है कि सड़कें केवल वाहनों के लिए नहीं हैं। पैदल यात्री, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांगजन सभी सड़क के बराबर अधिकार रखते हैं। सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध कराना सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी का हिस्सा है।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार।)

कब तक जारी रहेगा जहरीली शराब का जानलेवा कहर?

मनोज कुमार अग्रवाल

जहरीली शराब का यह जानलेवा सिलसिला देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर देखने को मिलता है एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बना हुआ है। ट्रांसनेशनल अलायंस टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रेड जैसी संस्थाओं के अनुसार, भारत में अवैध शराब की खपत दुनिया के सबसे बड़े अवैध बाजारों में से एक है। यह न केवल सरकारी राजस्व को भारी चोट पहुँचाता है, बल्कि इसके कारण हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है।

भारत में जहरीली शराब से होने वाली मौतें एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती बनी हुई हैं, जिसमें ड्राई स्टेट शराबबंदी वाले राज्यों से लेकर अन्य राज्यों तक लगातार दुखद घटनाएं सामने आती रहती हैं। ताजा मामला अगस्त 2026 में गुजरात के भावनगर का है, जहां नकली विदेशी शराब के नाम पर बेची गई जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं।

जहरीली शराब का यह जानलेवा सिलसिला देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर देखने को मिलता है एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बना हुआ है। ट्रांसनेशनल अलायंस टू कॉम्बैट इलिसिट ट्रेड जैसी संस्थाओं के अनुसार, भारत में अवैध शराब की खपत दुनिया के सबसे बड़े अवैध बाजारों में से एक है। यह न केवल सरकारी राजस्व को भारी चोट पहुँचाता है, बल्कि इसके कारण हर साल सैकड़ों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है देश भर में आए दिन जहरीली और नकली शराब से होने वाली मौतें अब केवल दुर्घटनाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ये घटनाएं हमारी व्यवस्था, कानून और समाज के सामने एक गंभीर सवाल हैं । कुछ दिन सप्ताह माह के अन्तराल पर देश के किसी न किसी हिस्से से खबर आती है कि नकली शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी, कई अस्पताल पहुंचे और कुछ ने दम तोड़ दिया। प्रशासन सक्रिय होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, जांच बैठती है, मुआवजे की घोषणा होती है और कुछ समय बाद मामला ठंडे बस्ते में पहुंच जाता है। फिर किसी दूसरे शहर, गांव या राज्य में वही कहानी दोहराई जाती है। सवाल यही है, आखिर यह सिलसिला कब थमेगा ?

आपको बता दें कि ताजा मामला गुजरात के भावनगर जिले का है। गुजरात उन राज्यों में है जहां लंबे समय से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भावनगर में कथित नकली शराब पीने के बाद कई लोगों की मौत और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की घटना सामने आई है। स्थानीय प्रशासन ने चार लोगों की मौत की जानकारी दी थी, जबकि अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था। शुरूआती रिपोटों में मौतों की संख्या कम थी, जो बाद में बढ़ी। यह घटना इसलिए भी अधिक गंभीर है, क्योंकि जिस राज्य में शराब की बिक्री और सेवन पर कानूनी प्रतिबंध है, वहां नकली शराब लोगों तक पहुंच कैसे रही है? पुलिस की शुरूआती जांच में एक लोकप्रिय ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट शराब बेचे जाने और इसके मध्य प्रदेश से लाए जाने की आशंका सामने आई है। पुलिस ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन भावनगर कोई पहली घटना नहीं है।हाल ही में मई माह में महाराष्ट्र

के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ त्रासदी इलाकों में जहरीली शराब पीने से 14 से 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस जांच के अनुसार, अवैध रूप से अधिक मुनाफा कमाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड का घातक मेथनॉल मिक्स किया गया था।मई माह में ही पंजाब के अमृतसर के पांच गांवों में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात ने जुलाई 2022 में भी भयावह शराब त्रासदी देखी थी। बोटाद और आसपास के इलाकों में जहरीली शराब से 42 लोगों की मौत हुई थी और दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। उस समय भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, अधिकारियों का तबादला हुआ और अवैध शराब के नेटवर्क को तोड़ने के दावे किए गए थे। सवाल है कि चार वर्ष बाद भी यदि नकली शराब लोगों तक पहुंच रही है तो पिछली कार्रवाई से हमने आखिर सीखा क्या? यह समस्या केवल गुजरात तक सीमित नहीं है। पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्य समय-समय पर ऐसी त्रासदियों के गवाह बने हैं। तमिलनाडु के कालाकुरिची में जून 2024 में मेथेनॉल मिली अवैध शराब ने दर्जनों परिवारों को उजाड़ दिया था। आधिकारिक कार्रवाई के दौरान अवैध शराब जब्त हुई, गिरफ्तारियां हुई और प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में भी अवैध एवं नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। उपलब्ध एनसीआरबी आधारित डेटा 2012 से 2024 तक राज्य वार ऐसी मौतों का हवाला देता है। इससे इतना तो साफ है कि यह किसी एक राज्य या एक क्षेत्र विशेष की समस्या नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही एक खतरनाक चुनौती है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अक्सर इन घटनाओं में मरने वाले लोग समाज के आर्थिक रूप से दुर्बल कमजोर वर्ग से आते हैं। सस्ती शराब की तलाश उन्हें ऐसे अवैध कारोबारियों तक पहुंचा देती है जिन्हें न गुणवत्ता की चिंता होती है, न कानून का भय और न इंसानी जीवन की कीमत का एहसास। अधिक नशा पैदा करने या लागत कम रखने के लिए शराब में मेथेनॉल जैसे जहरीले रसायनों की मिलावट जानलेवा साबित हो सकती है। कल्लाकुरिची मामले में भी मेथेनॉल मिश्रित शराब की पुष्टि सामने आई थी। अधिकरत देखा जाता है कि हर बड़ी आसदी के बाद प्रशासन की एक परिचित तस्वीर सामने आती है। छापेमारी शुरू होती है, अवैध ठिकाने बंद किए जाते हैं, संदिग्ध गिरफ्तार होते हैं और पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है। लेकिन असली चुनौती घटना के बाद कार्रवाई करने की नहीं, घटना होने से पहले नेटवर्क को समाप्त करने की है। अवैध शराब का कारोबार अकेले किसी गली या गांव में बैठा व्यक्ति नहीं चला सकता। कच्चा माल कहां से आता है? बोतलें कहां बनती हैं? लोकप्रिय कंपनियों के नाम और लेबल की नकल कैसे होती है? माल एक जिले से दूसरे जिले और कई बार एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचता है? परिवहन, भंडारण और बिक्री की जानकारी स्थानीय स्तर पर किसी को क्यों नहीं मिलती? यदि वर्षों तक कारोबार चलता रहता है तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही, स्थानीय संरक्षण या भ्रष्ट तंत्र भी इसका रास्ता आसान कर रहा है। शराबबंदी वाले राज्यों के लिए यह समस्या और बड़ी चुनौती है। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता। यदि वैध बिक्री बंद होने के बाद अवैध बाजार पैदा हो जाए और उसकी निगरानी कमजोर रहे तो तस्करों को अधिक मुनाफे का अवसर मिलता है। शराबबंदी का उद्देश्य समाज को नशे से बचाना है, लेकिन यदि उसी व्यवस्था के भीतर जहरीली शराब का संगठित बाजार फलने लगे तो नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन दोनों जरूरी हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि शराबबंदी गलत है या शराब की खुली बिक्री समाधान है। असली प्रश्न नीति से अधिक उसके प्रभावी क्रियान्वयन का है। जहां प्रतिबंध है वहां अवैध सप्लाई पर कठोर निगरानी होनी चाहिए और जहां शराब की कानूनी बिक्री है वहां नकली उत्पादों की पहचान और वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण मजबूत होना चाहिए। सरकारों को अब प्रत्येक त्रासदी के बाद केवल मुआवजा देने और कुछ लोगों को निलंबित करने से आगे बढ़ना होगा। अवैध शराब के मामलों में सप्लाई चेन की तह तक जांच, औद्योगिक मेथेनॉल की बिक्री और परिवहन की निगरानी, नकली ब्रांड और पैकेजिंग बनाने वालों पर कार्रवाई तथा बार-बार अवैध कारोबार में पकड़े जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई जरूरी है।यह सारा अवैध कारोबार बिना सरकारी तंत्र की मिलीभगत के सम्भव नहीं है स्थानीय पुलिस और आबकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण और गरीब बस्तियों में जागरूकता बढ़ानी होगी। लोगों को बताया जाना चाहिए कि अनजान स्रोत से खरीदी गई शराब जानलेवा हो सकती है। संदिग्ध शराब पीने के बाद उल्टी, चक्कर, दृष्टि धुंधली होने वा अन्य परेशानी के मामलों में तुरंत अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी है। कई बार इलाज में देर भी मौतों की संख्या बढ़ा देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहरीली शराब से हुई हर मौत को महज एक आंकड़ा समझने की मानसिकता बदलनी होगी। मरने वाला किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य, बेटा, पिता या भाई होता है। उसके जाने के बाद परिवार केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक संकट में भी डूब जाता है। देश में तकनीक बड़ी है, पुलिस के पास आधुनिक संसाधन हैं, राज्यों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान पहले से आसान हुआ है। ऐसे में यह स्वीकार करना मुश्किल है कि अवैध शराब की पेटियां एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचे और व्यवस्था को भनक तक न लगे। भावनगर की घटना फिर चेतावनी दे रही है कि नकली शराब केवल कानून-व्यवस्था का सवाल नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा का प्रश्न है। कार्रवाई तब सार्थक होगी जब अगली त्रासदी होने से पहले अपराधी नेटवर्क खत्म किया जाए। हर घटना के बाद वही सवाल पूछने की मजबूरी आखिर कब समाप्त होगी, कब थमेगा जहरीली शराब का कहर और कब बंद होगा बेगुनाहों की मौतों का यह सिलसिला। एक मौत पूरे परिवार को मार देती है कई बार परिवार के एक मात्र कमाने वाले सदस्य की मौत से पूरा परिवार प्रभावित होता है। सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

प्रिंस हैरी शाही भूमिकाओं के बिना ब्रिटेन लौटेंगे; भारतीय महिला को इस्राइल में अच्छी नागरिकता सम्मान

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन ने यूनाइटेड किंगडम लौटने का फैसला किया है। हालांकि, वे शाही परिवार के कामकाजी सदस्यों के रूप में अपनी भूमिकाएं फिर से शुरू नहीं करेंगे। किंग चार्ल्स को रविवार को इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया। हालांकि, पिछले महीने दंपती की यूके यात्रा के दौरान उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया था। डेली टेलीग्राफ ने यह खबर सबसे पहले प्रकाशित की है। अखबार के अनुसार, हैरी और मेघन के बच्चे, प्रिंस आर्ची (7) और प्रिंसेस लिलिबेट (5), ब्रिटिश स्कूलों में पहले ही दाखिला ले चुके हैं। वे सितंबर में अपनी कक्षाएं शुरू करेंगे। यह निर्णय दंपती द्वारा अपनी शाही जिम्मेदारियां छोड़ने के छह साल से अधिक समय बाद आया है। उन्होंने आकर्षक मीडिया अनुबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया का रुख किया था। ब्रिटेन लौटने से किंग चार्ल्स को अपने पोते-पोतियों से अधिक मिलने का अवसर मिलेगा। किंग चार्ल्स एक अज्ञात प्रकार के कैंसर का इलाज करा रहे हैं। दंपती ने छह साल से अधिक समय पहले अपने शाही कर्तव्यों को त्याग दिया था। वे कैलिफोर्निया में बस गए थे। इस वापसी से परिवार के संबंधों में मजबूती आ सकती है।

इस्राइल में देखभाल करने वाली भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता का सम्मान

यरुशलम, एजेंसी। इस्राइल पुलिस ने एक भारतीय महिला को अच्छी नागरिकता के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया है। देखभाल करने वाली इस महिला ने कार्मेल क्षेत्र में 95 वर्षीय होलोकॉस्ट पीड़ित को ठगी के प्रयास से बचाया था। बुधवार को तटीय जिला पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में हाइफा पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने हीरा (हीराबेन) को यह प्रमाण पत्र प्रदान किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हीराबेन उस बुजुर्ग महिला की नर्सिंग देखभालकर्ता यानी केयरगिवर के रूप में काम कर रही हैं। इजरायल में कुछ ही महीने रहने के बावजूद, हीराबेन ने सूझबूझ और साहस का परिचय दिया। उन्होंने महिला को एक कथित धोखेबाज से बचाया, जो क्लैलित हेल्थ सर्विसेज की नर्स बनकर उनके अपार्टमेंट में आया था। देखभालकर्ता ने शांत रहते हुए घटना को दर्ज किया, संदिग्ध को बुजुर्ग महिला के पास जाने से रोका और पुलिस को सूचित किया। इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और संदिग्ध की हिरासत दो दिन पहले कानूनी कार्रवाई पूरी होने तक बढ़ा दी गई थी। जांचकर्ता नोफर पाज़ ने बुजुर्ग महिला और उनके परिवार की उपस्थिति में हीराबेन को धन्यवाद दिया।

सफारी के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश, पांच अमेरिकी समेत सात लोगों की मौत

नैरोबी, एजेंसी। केन्या के उत्तरी हिस्से में बुधवार सुबह सफारी के दौरान एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस और अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक शामिल थे। हेलीकॉप्टर सुबह 9ः13 बजे लॉइसाबा कंजरवेंसी से साम्बुरु काउंटी के इवासो न्यिरो इलाके की ओर जा रहा था। केन्या नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, हेलीकॉप्टर में कुल सात लोग सवार थे। इनमें छह यात्री और एक पायलट था। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। साम्बुरु के पुलिस कमांडर डेविड नकोरोई ने बुधवार देर शाम पुष्टि की कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मौत हो गई है। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि मृतकों में पांच अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी दूतावास स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और पीड़ितों से जुड़े लोगों को जरूरी कांसुलर सहायता उपलब्ध करा रहा है। मृतकों की आधिकारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित एक स्थानीय टीवी स्टेशन ने बताया कि मृतकों में जोस सुआरेज भी शामिल थे, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी और वह टेलीमुंडो के फ्लोरिडा स्थित कई स्टेशनों के अध्यक्ष और महाप्रबंधक थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार, हेलीकॉप्टर माउंट ओलोलोक्वे की तलहटी में स्थित एक दुर्गम और ऊबड़-खाबड़ इलाके में गिरा। यह स्थान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। हेलीकॉप्टर स्थानीय कंपनी लेडी लॉरी हेलीकॉप्टर्स का था और चार्टर उड़ान के तहत यात्रियों को ले जा रहा था। सफारी कंपनी एंडबियॉन्ड के साथ यात्रा कर रहे लोगों के लिए यह उड़ान संचालित की गई थी। ट्रॉपिक एयर केन्या ने तलाश और बचाव अभियान में मदद के लिए अपने दो हेलीकॉप्टर भेजे। केन्या रेड क्रॉस की आपातकालीन टीमें भी बहु-एजेंसी राहत अभियान में शामिल हुईं।

गंगा जल पर फिर तनातनीः गारंटी प्रावधान मांगने की तैयारी में बांग्लादेश, क्या भारत से बिगड़ेंगे रिश्ते

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश ने भारत के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पड़ोसी मुल्क अब नई संधि में 'गारंटी प्रावधान' शामिल करने की मांग करेगा। साथ ही उसने संकेत दिया है कि पानी के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख भी किया जा सकता है। जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने मंगलवार को ढाका में आयोजित एक संगोष्ठी में यह बात कही। संगोष्ठी का विषय था- 'गंगा जल संधिः पुनर्विचार के मुद्दे'। इसका आयोजन बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ने किया था। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने इसकी जानकारी दी।

दिसंबर में समाप्त होने वाली है गंगा जल संधि : भारत और बांग्लादेश के बीच 1996 में हुई गंगा जल संधि दिसंबर में समाप्त होने वाली है। यह संधि सूखे मौसम में गंगा के पानी के बंटवारे की व्यवस्था करती है। अनी ने कहा कि बांग्लादेश संधि पर दोबारा बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान अगले महीने संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश का पक्ष मजबूती से रखेंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को संधि चाहिए। उनके मुताबिक, बिना संधि के आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है और यह बांग्लादेश का अधिकार है।

क्या 1977 वाला गारंटी प्रावधान फिर लौटेगा : अनी ने भविष्य की जल-बंटवारा संधियों में सूचना के अधिकार से जुड़ा प्रावधान शामिल करने की जरूरत बताई। उन्होंने 1977 की गंगा संधि में मौजूद 'गारंटी प्रावधान' को फिर शामिल करने की मांग की। यह प्रावधान 1996 की संधि में नहीं रखा गया था। गारंटी प्रावधान का मतलब है कि निचले हिस्से वाले देश को पानी की न्यूनतम मात्रा मिलने की गारंटी हो। इसका उद्देश्य सूखे मौसम या नदी का जलस्तर अचानक घटने पर पानी की आपूर्ति को सुरक्षित रखना है।

बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि सबसे सूखे मौसम में पर्याप्त पानी की गारंटी नहीं देती। उसकी आपत्ति यह भी है कि पानी बांटने का मौजूदा तरीका पुराने जलवैज्ञानिक हालात पर आधारित है। सूखे मौसम में नदी का प्रवाह अब ज्यादा अनिश्चित हो गया है। बांग्लादेश पर्यावरण से जुड़े प्रावधानों को भी अपर्याप्त मानता है। वह ऊपरी हिस्से में पानी की निकासी, नदी के स्वास्थ्य, बढ़ती लवणता और पारिस्थितिक प्रवाह को भी चर्चा में शामिल करना चाहता है।

क्या फरक्का बैराज फिर बनेगा विवाद का केंद्र : भारत-बांग्लादेश जल संबंधों में फरक्का बैराज लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत द्वारा बनाए गए इस बैराज का उद्देश्य गंगा के पानी के एक हिस्से को हुगली नदी तंत्र की ओर मोड़ना है। बांग्लादेश में इसे लेकर लंबे समय से चिंता रही है कि इससे सूखे मौसम में नीचे की ओर पानी का प्रवाह कम होता है। अनी ने कहा कि बांग्लादेशी लोग लंबे समय से फरक्का बैराज को 'मौत का जाल' मानते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि फरक्का के बाद भारत ने गंगा पर बैराज और करीब 900 तटबंध बनाए, जिससे दोनों देशों के संबंधों पर दबाव पड़ा।

भारत का रुख क्या : भारत का कहना है कि फरक्का बैराज बांध नहीं, बल्कि पानी को मोड़ने वाली संरचना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इसके द्वारों की व्यवस्था के जरिए गंगा के करीब 40,000 क्यूसेक पानी को फरक्का नहर में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी पानी बांग्लादेश की ओर बहता रहता है। भारत यह भी कहता है कि समझौते के तहत जल प्रवाह का आंकड़ा संयुक्त नदी आयोग के जरिए बांग्लादेश के साथ नियमित रूप से साझा किया जाता है। बांग्लादेश और भारत के बीच 54 प्रमुख नदियां साझा हैं। गंगा दोनों देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीमा-पार नदियों में से एक है। जल बंटवारे और नदी से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश संयुक्त नदी आयोग के जरिए बातचीत करते हैं।

क्या भारत जल्द शुरू करेगा नई संधि पर बातचीत : जुलाई में भारत की विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर बिना और देरी के बातचीत शुरू करने को कहा था। समिति ने सिफारिश की थी कि बातचीत में नए जलवैज्ञानिक आंकड़ों, जलवायु अनुमानों और पश्चिम बंगाल तथा बिहार की चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। भारत सरकार ने फरवरी में संसद को बताया था कि संधि के नवीनीकरण को लेकर बांग्लादेश के साथ बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार ने यह भी कहा था कि पश्चिम बंगाल सरकार सहित संबंधित पक्षों से मिले सुझावों को भारत का रुख तय करते समय ध्यान में रखा गया है। अनी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब इससे दो दिन पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश तीस्ता नदी के लंबे समय से लंबित जल-बंटवारा समझौते को लेकर भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने भारत से अपने हितों के साथ बांग्लादेश के हितों को भी ध्यान में रखने की अपील की थी।

नताली हार्प बनीं ट्रंप की सबसे भरोसेमंद साथी, कैमरे से दूर रहकर कैसे बढ़ा व्हाइट हाउस में असर

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास कई ताकतवर लोग हैं, लेकिन 35 वर्षीय नताली हार्प की भूमिका अलग नजर आती है। वह कैमरे के सामने बोलने वाली अधिकारी नहीं हैं, फिर भी ट्रंप के आसपास लगातार दिखाई देती हैं। ओवल ऑफिस से लेकर मरीन वन तक वह राष्ट्रपति के साथ रहती हैं। खास तौर पर प्रेस सचिव रहीं केरोलिन लेविट की विदाई के बाद व्हाइट हाउस में हार्प की अहमियत और बढ़ने की बात सामने आई है।

नताली हार्प को ह्यूमन प्रिंटर क्यों कहा जाता है : हार्प ट्रंप के लिए लगातार जानकारी जुटाने, विश्व नेताओं से संदेशों के आदान-प्रदान और सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करने में मदद करती हैं। वह देर रात तक राष्ट्रपति के साथ काम करती हैं और रविवार को भी छुट्टी नहीं लेने की बात सामने आई है। उनके पास एक पोर्टेबल प्रिंटर भी रहता है। इसी वजह से व्हाइट हाउस में उन्हें 'ह्यूमन प्रिंटर' कहा जाता है। वह ट्रंप तक सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया की जानकारी तुरंत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं।

ट्रंप के साथ खतरनाक सफर में भी क्यों रहीं : नताली की भूमिका उस समय भी चर्चा में आई जब वह एक बेहद गुप्त अभियान का हिस्सा बनीं। इस अभियान में हमले के खतरे के बीच ट्रंप और कुछ चुनिंदा लोगों को तुर्किये से सुरक्षित

निकालने की कोशिश की गई थी। इसके लिए विमान के कैटरिंग कंटेनर का इस्तेमाल किया गया था। इस घटना के बाद हार्प की भूमिका ज्यादा लोगों की नजर में आई। ट्रंप के करीबी सहयोगियों के अनुसार, राष्ट्रपति के प्रति उनकी निष्ठा बेहद मजबूत है।

ट्रंप से नताली का रिश्ता इतना खास कैसे बना : हार्प की ट्रंप से नजदीकी का एक निजी कारण भी बताया जाता है। वह कैंसर से जूझ चुकी हैं। उनके अनुसार, ट्रंप की ओर से समर्थित 'राइट टू ट्राई' कानून ने उन्हें प्रयोगात्मक इलाज तक पहुंच दिलाने में मदद की और इससे उनकी जिंदगी बचाने में मदद मिली। ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि दूसरे कर्मचारी भविष्य में उनका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन नताली ऐसा नहीं करेंगी। यही निजी अनुभव दोनों के बीच भरोसे की एक वजह माना जाता है। हाल ही में सामने आए पत्रों में नताली ने ट्रंप के प्रति अपनी बेहद गहरी निष्ठा जाहिर की थी।

यूएनएससी में भारत की दो टूकः विकासशील देशों को मिले अधिक प्रतिनिधित्व, आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के काम करने के तरीकों पर खुली चर्चा हुई। इस चर्चा में भारत की राजदूत योजना पटेल ने देश का पक्ष रखा।उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण यानी विकासशील देशों को सुरक्षा परिषद में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में सार्थक योगदान देने का मौका मिलना चाहिए। इसके लिए सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को दस्तावेजों तक पहुंच के मामले में एक जैसे अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए।

राजदूत योजना पटेल ने क्या कहा : योजना पटेल ने कहा कि जो देश सीधे तौर पर किसी मुद्दे से जुड़े हैं, उन्हें सुरक्षा परिषद के फैसले लेने की व्यवस्था में भी शामिल किया जाना चाहिए। खासकर शांति स्थापना से जुड़े सभी बड़े सवालों में उनकी भूमिका होनी चाहिए। इनमें मिशन का काम क्या होगा और उसके लिए कितने संसाधन दिए जाएंगे जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज संख्या- 507 में उचित बदलाव किया जाना चाहिए। इसमें सुरक्षा परिषद की सहायक संस्थाओं के अध्यक्षों के नाम तय करने के लिए स्पष्ट और अंतिम समय-सीमा होनी चाहिए। यह समय-सीमा ऐसी होनी चाहिए, जिस पर कोई समझौता न हो सके।

आतंकवाद पर राजनीति को लेकर क्या कहा : भारत ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद को छोटे और सीमित राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का मंच नहीं बनना चाहिए। योजना पटेल ने कहा कि सुरक्षा परिषद में किसी देश की मौजूदगी का इस्तेमाल आतंकवादियों को वैध ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक कारणों के आधार पर आतंकियों को आतंकवादी सूची से हटाने या दूसरी संस्थाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निष्पक्ष मापदंड और समर्थन करने वाले दस्तावेज होना जरूरी है।

अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग, भागवत के यूएस दौरे पर यूएससीआईआरएफ सख्त; बोला- संघ नेताओं को न मिले सम्मान

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली सलाहकार संस्था यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (यूएससीआईआरएफ) के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अमेरिकी सरकार से अपील की है कि वह आरएसएस नेताओं को राजनयिक सम्मान न दे और न ही उनके साथ किसी तरह की हाई-लेवल मीटिंग करे। यह बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के प्रस्तावित अमेरिका दौरे से पहले आया है। वहीं, भारत पहले ही यूएससीआईआरएफ की रिपोर्टों को पक्षपातपूर्ण और वैचारिक पूर्वाग्रह पर आधारित बताते हुए खारिज कर चुका है। आरएसएस नेताओं से दूरी बनाने की अपील यूएससीआईआरएफ के चेयरमैन

आसिफ महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक %अंब्रेला ऑर्गनाइजेशन यानी ऐसा मुख्य संगठन बताया, जिसके सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के आरोप लगते रहे हैं। महमूद की ये टिप्पणियां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे से कुछ हफ्ते पहले सामने आई हैं। भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग की ओर से आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन (एकता का उत्सव) में शामिल होने वाले हैं। आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध की मांग यूएससीआईआरएफ कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि आरएसएस नेताओं को, भले ही वे भारत सरकार से जुड़े हों, हाई-लेवल मीटिंग या राजनयिक सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय, अमेरिकी सरकार को उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने पर ध्यान देना चाहिए, जो फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ यानी धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। यूएससीआईआरएफ ने आसिफ महमूद और जीन मिल्स की इन टिप्पणियों को अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। महमूद ने आरएसएस को लेकर क्या कहा महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य हैं। यह भारत का एक मुख्य संगठन है, जिसके सहयोगी समूहों ने ईसाइयों और मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। अब आरएसएस नेता मोहन भागवत अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी उठाए सवाल एडवोकेसी ग्रुप हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि मोहन भागवत के दौरे को मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क से जुड़े हिंसा के आरोपों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

विदेशों का नया ट्रेंड भारत की पुरानी जीवनशैली है ब्रिटेन-अमेरिका के जेन-जी अपना रहे भारतीय साइलेंट वॉक

लंदन, एजेंसी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों में जेन-जी के बीच इन दिनों साइलेंट वॉकिंग तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इसमें युवा मोबाइल फोन को दूर रखकर, ईयरफोन उतारकर और बिना संगीत या पॉडकास्ट सुने चुपचाप टहलते हैं। सोशल मीडिया पर इसे तनाव कम करने और मानसिक सुकून पाने के तरीके के रूप में पेश किया जा रहा है। हालांकि भारतीयों के लिए यह तरीका उतना नया नहीं है, क्योंकि यहां मौन और एकांत में टहलने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है।

क्या है साइलेंट वॉकिंग और युवा इसे क्यों अपना रहे हैं : साइलेंट वॉकिंग का मतलब बिना किसी डिजिटल गतिविधि के पैदल चलना है। इस दौरान मोबाइल, संगीत, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक और सोशल मीडिया से दूरी बनाई जाती है। व्यक्ति केवल अपने कदमों, विचारों और

आसपास के वातावरण पर ध्यान देता है। लगातार फोन और इंटरनेट से जुड़े रहने वाली युवा पीढ़ी के लिए यह तरीका कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से दूरी बनाने का अवसर देता है। इसे तनाव कम करने और मन को शांत करने के एक आसान तरीके के रूप में देखा जा रहा है। क्या भारत में यह परंपरा पहले से मौजूद है भारत में मौन और एकांत को मानसिक शांति से जोड़ने की परंपरा सदियों पुरानी है। मंदिरों की परिक्रमा, मौन व्रत और विपश्यना जैसे अभ्यासों में बाहरी शोर से दूरी बनाकर आत्मचिंतन पर जोर दिया जाता है। मंदिर परिसरों और पार्कों में चुपचाप टहलना भी भारतीय जीवनशैली का हिस्सा रहा है। इसलिए पश्चिमी देशों में साइलेंट वॉकिंग का बढ़ता चलन भारतीय नजरिए से किसी बिल्कुल नई चीज के बजाय पुरानी परंपरा के आधुनिक रूप जैसा दिखाई देता है।

क्या भारतीय युवा भी इसे अपना रहे हैं : भारत में भी युवा बिना ईयरफोन और मोबाइल में व्यस्त हुए सार्वजनिक जगहों पर टहलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली का लोधी गार्डन, बंगलूरू का कब्बन पार्क और मुंबई का मरीन ड्राइव ऐसे स्थान हैं, जहां लोग चहलकदमी करते हैं। हालांकि भारत में इसे हमेशा साइलेंट वॉकिंग के नाम से नहीं जाना जाता। पश्चिम में इसके लिए एक नया नाम और सोशल मीडिया ट्रेंड बन गया है, जबकि भारत में इसके पीछे की आदत और विचार लंबे समय से मौजूद हैं।

2023 में सोशल मीडिया पर कैसे लोकप्रिय हुआ यह नाम : साइलेंट वॉकिंग की अवधारणा पुरानी है, लेकिन इसका नाम 2023 में सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुआ। टिकटॉक क्रिएटर मैडी माओ ने बिना फोन, संगीत और पॉडकास्ट के 30 मिनट टहलने का अपना अनुभव साझा किया था। इसके बाद यह तरीका सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। धीरे-धीरे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड और बेल्जियम समेत कई पश्चिमी देशों के युवाओं ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। साइलेंट वॉकिंग के बढ़ते चलन में डिजिटल दुनिया से थोड़ी देर दूरी बनाने की कोशिश साफ दिखाई देती है।

ईरान पर होगी सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाईः ट्रंप ने दी धमकी, मदद करने वाले देशों को चेताया; क्या बढ़ेगा तनाव

वाशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया था। लेकिन उसने इसे गंवा दिया।

ट्रंप ने कहा, इस्लामी गणराज्य ईरान को किसी समझौते के लिए मुझसे ज्यादा बड़ा मौका किसी ने नहीं दिया। दुख की बात है कि उन्होंने इस मौके का फायदा नहीं उठाया। इसलिए आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा कर रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायु सेना नष्ट हो गई है। उसकी सैन्य फैक्टरियां मलबे में बदल गई हैं। ईरान की मुद्रा बेकार हो गई है और देश बेहद कमजोर स्थिति में है।

ईरान की मदद करने वाले देशों पर भी कार्रवाई : ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद देगा, उसे भी बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसमें वित्तीय संस्थान, कारोबार, हवाई अड्डे और सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने तेल की तस्करी, स्वैप लाइन, नकद लेनदेन, एक्सचेंज हाउस, जहाजों के पंजीकरण और ईरान की मदद करने वाली छिपी हुई (शेल) कंपनियों को तुरंत रोकने की बात कही।

सहयोगी देशों से अमेरिका के साथ आने की अपील : ट्रंप ने इसे ईरान के खिलाफ बड़े आर्थिक हमले का दिन बताया। उन्होंने अमेरिका के सहयोगी देशों से ईरान को अलग-थलग करने और उसके खतरे को खत्म करने में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय बेहद कमजोर स्थिति में है।

उन्होंने दावा किया कि ये ऐतिहासिक कदम ईरान को और दुनियाभर में आतंक फैलाने की उसकी क्षमता को बुरी तरह कमजोर कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा।

अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया : अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के पिछले हफ्ते इसी तरह बयान दिया था। बेसेंट ने कहा था कि अमेरिका ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिशें बढ़ाएगा। इस रणनीति में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी भी शामिल है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय %ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी% नाम से प्रतिबंध अभियान भी चला रहा है। इसका मकसद लक्षित कार्रवाई के जरिये ईरान के पैसे जुटाने के स्रोतों को बंद करना है। युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के साथ हुई। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने ईरान को सैन्य उपकरण और ड्रोन से जुड़ी तकनीक दी है। वहीं, चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। चीन ने ईरान के साथ कारोबारी रिश्ते बनाए रखे हैं और उसे कूटनीतिक समर्थन भी दिया है।

कौन हैं अमेरिका की एफडीए प्रमुख बनने जा रहीं हेइडी ओवरटन, ट्रंप ने किया नामित, विवादों से भी रहा है नाता

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी डॉ. हेइडी ओवरटन को खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए का अगला आयुक्त बनाने के लिए नामित किया है। अगर अमेरिकी सीनेट उनकी नियुक्ति को मंजूरी देती है, तो वह इस बेहद महत्वपूर्ण संस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। एफडीएअमेरिका में दवाओं, वैक्सीन, चिकित्सा उपकरणों और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और नियमन से जुड़े बड़े फैसले करता है। ओवरटन फिलहाल व्हाइट हाउस के घरेलू नीति परिषद में उपनिदेशक के पद पर हैं और ट्रंप प्रशासन की स्वास्थ्य नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं।

ओवरटन की पढ़ाई और करियर कितना मजबूत : हेइडी ओवरटन मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से मेडिकल की पढ़ाई की। इसके बाद जॉन्स हॉपकिन्स में जनरल सर्जरी का प्रशिक्षण लिया और क्लिनिकल जांच से जुड़ी उच्च शिक्षा भी हासिल की। ट्रंप प्रशासन में आने से पहले वह कंजर्वेटिव थिंक टैंक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट में मुख्य नीति अधिकारी के रूप में काम कर चुकी हैं। यानी उनका अनुभव केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य नीति और राजनीतिक प्रशासन से भी जुड़ा रहा है।

ट्रंप के भरोसेमंद लोगों में कैसे शामिल हुईं : दूसरे कार्यकाल में ओवरटन ट्रंप की कई स्वास्थ्य योजनाओं में उनके साथ दिखाई दी हैं। दवा की कीमत कम करने, नई दवाओं को तेजी से मंजूरी देने और स्वास्थ्य नीति में बदलाव से जुड़े कई कार्यक्रमों में उन्होंने भूमिका निभाई है। ट्रंप ने उनके नाम की घोषणा करते हुए उन्हें बेहद सक्षम और भरोसेमंद अधिकारी बताया तथा तेज इलाज, चिकित्सा नवाचार और दवाओं की कम कीमत जैसे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने भी ओवरटन के फैसले लेने की क्षमता और प्रशासनिक अनुशासन की तारीफ की है।

वैक्सीन नीति को लेकर क्यों उठे सवाल : ओवरटन की नियुक्ति का

सबसे विवादित पक्ष उनकी वैक्सीन नीति से जुड़ी भूमिका है। हाल में वह उस कार्यक्रम में ट्रंप के साथ खड़ी थीं, जिसमें बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी नीति में बड़े बदलावों की घोषणा की गई थी। इसमें खसरा, कण्ठमाला और रूबेला यानी एमएमआर वैक्सीन को अलग-अलग टीकों में बांटने की योजना भी शामिल थी। चिकित्सा जगत के कई लोगों ने इस नीति पर सवाल उठाए हैं। इसी वजह से ओवरटन की एफडीएमें संभावित भूमिका को लेकर वैज्ञानिक और स्वास्थ्य क्षेत्र में बहस तेज हो गई है।

गर्भपात की दवाओं पर क्या है ओवरटन का रुख : ओवरटन गर्भपात की दवाओं को लेकर भी सख्त रुख रखती हैं। वह ऐसी दवाओं की उपलब्धता और ऑनलाइन इस्तेमाल से जुड़ी मौजूदा व्यवस्था की आलोचना कर चुकी हैं। अगर सीनेट से उनकी नियुक्ति मंजूर होती है, तो स्नष्ठ के सामने गर्भपात की दवाओं से जुड़े नियमों की समीक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अमेरिका में गर्भपात को लेकर पहले से ही राजनीतिक और कानूनी विवाद चल रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर ओवरटन के फैसलों पर खास नजर रहेगी।

एफडीएको संभालते ही किन बड़ी चुनौतियों का सामना होगा : ओवरटन ऐसे समय एफडीए की कमान संभाल सकती हैं, जब संस्था पहले ही नेतृत्व और कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है। पूर्व आयुक्त डॉ. मार्टी मकारी ने मई में पद छोड़ दिया था। उनके कार्यकाल में ई-सिगरेट, गर्भपात की दवाओं और नई दवाओं की मंजूरी जैसे मुद्दों पर विवाद रहे। एफडीए में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के जाने से भी संस्था पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में नई प्रमुख से प्रशासनिक स्थिरता और जनता का भरोसा बहाल करने की उम्मीद होगी।

क्या दवाओं की मंजूरी का तरीका भी बदल सकता है : एफडीए की एक बड़ी जिम्मेदारी नई दवाओं और चिकित्सा उत्पादों की जांच तथा मंजूरी देना है। ट्रंप प्रशासन तेज मंजूरी और चिकित्सा नवाचार को बढ़ावा देने की बात करता रहा है। दूसरी ओर, एफडीए से जुड़े वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुरक्षा मानकों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत पर जोर देते हैं। ओवरटन को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। खासकर दुर्लभ बीमारियों की दवाओं, जैव-तकनीकी उत्पादों और नई चिकित्सा तकनीकों से जुड़े फैसले उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौती होंगे। एफडीए केवल दवाओं और वैक्सीन तक सीमित नहीं है। खाद्य सुरक्षा भी उसकी जिम्मेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने अल्ट्राप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों को लेकर लगातार सवाल उठाए हैं।

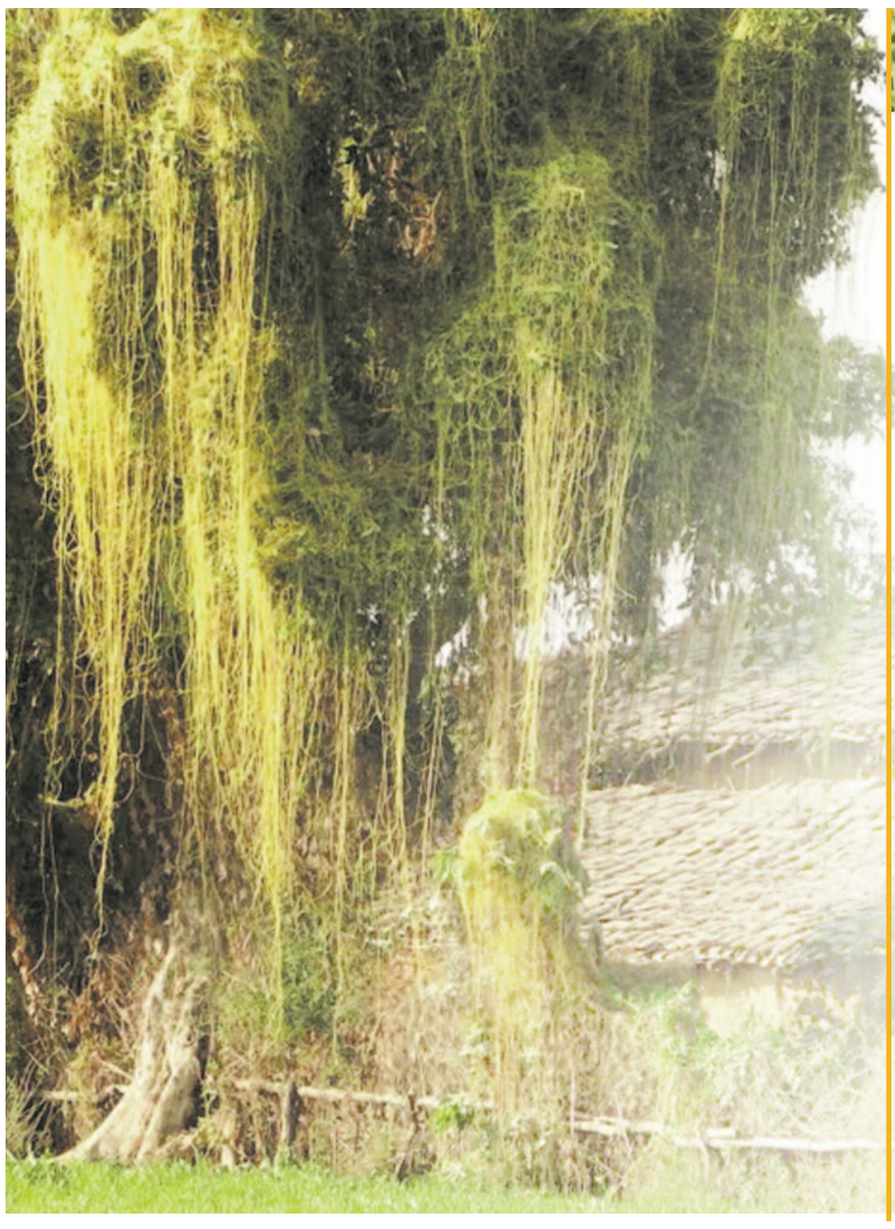

मोटे अनाजों में प्रमुख

बाजरा

भूमि का चुनाव

बाजरे की असिंचित फसल उन मिट्टियों में अच्छी उपज देती है, जिनकी जलधारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। रेतीली मटियार दोमट और मटियार दोमट भूमि में बाजरा की भरपूर पैदावार होती है।

भूमि की तैयारी

बाजरा वर्षा आधारित फसल है। ऐसी फसल के लिए गर्मियों की जुताई अच्छी पाई गई है। इससे खरपतवारों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। वर्षा के शुरू होने पर हल या बखर चलाकर खेत को भुरभुरा बनायें तथा खरपतवार रहित करें।

उन्नत किस्में

अ. संकर किस्में - आईसीएमएच-356, जवाहर बाजरा हायब्रिड-1, जवाहर बाजरा हायब्रिड-2, हरित बटल रोग निरोधक

ब. परागित किस्में - जवाहर बाजरा किस्म-2, जवाहर बाजरा किस्म-3, जवाहर बाजरा किस्म-4, राज-171

बुआई

बाजरा की बुआई के लिए जुलाई का पहला पखवाड़ा ही उत्तम है। इस समय पर लगाए गए बाजरा पर रोगों का प्रकोप कम होता है तथा फूल आते समय सामान्य वर्षा होने पर प्रायः भूमि

में नमी का अभाव नहीं होता है।

बीज की मात्रा और पौधों का घनत्व

बाजरा की संकर किस्मों की कतारों के बीच 45 सेमी की दूरी रखना जरूरी है, जिसमें पौधों से पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेमी होना चाहिए। बीज 1 से 2.5 सेमी की गहराई पर बोना चाहिए। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 1.8 लाख से 2 लाख तक उचित पौध संख्या के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा पर्याप्त रहती है। बुआई के पूर्व बीजोपचार जरूरी है बीज का उपचार एग्रान-35 एसडी की 6 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, जिससे डाउनी मिल्डयू रोग के प्रारंभिक प्रकोप से बचा जा सके।

उर्वरक की मात्रा एवं देने का तरीका

बुआई के पूर्व 87 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम और 33 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर देना चाहिए।

पौधों की छटाई

बाजरा के पौधें के पूर्ण विकास के लिए उपयुक्त स्थान मिलना आवश्यक है। अतः घने पौधों की छंटाई करके पौधों की आपसी दूरी उपयुक्त कर देनी चाहिए।

जल प्रबंध

बाजरा का केवल 3.3 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। अतः जल का समुचित प्रबंध करना सफल खेती और उत्पादन स्थिरता की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। वर्षा का केवल 5-15 प्रतिशत जल पौधों की बढ़वार के लिए उपलब्ध हो पाता है। इस प्रकार बाजरा उगाने वाले क्षेत्रों में जल का वैज्ञानिक प्रबंधन ही उनकी सफल खेती में सहायक हो सकता है। भूमि तल को समतल बना देने पर भूमि पर गिरने वाली वर्षा का समान वितरण होता है। तथा पानी भूमि में लम्बे समय तक भरे रहने के कारण इसका उत्तम संरक्षण करना संभव होता है। मेड़ बांधने की क्रिया जल संरक्षण में काफी सहायक पायी गयी है। वर्षा जल खेत में लम्बे समय तक खड़े रहने के कारण बहाव के माध्यम से बह जाने वाले जल की अधिक से अधिक मात्रा भूमि द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा यह मात्रा भूगत होने के कारण सुरक्षित रहती है। यह विश्वास किया जाता है कि भूमि की ऊपरी सतह को संहत करने पर बाजरा के पौधे की जड़े अधिक गहराई तक जाती है जिसके कारण उपलब्ध भूमि जल का अच्छा उपयोग होता है तथा जड़ों का जल ग्रहण क्षेत्र भी बढ़ जाता है। इस क्रिया को शायद इसी कारण से मूल प्रशिक्षण (रुट ट्रेनिंग) भी कहा जाता है। क्योंकि जड़ों के नीचे की और बढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानि कि ऐसी स्थिति बनायी जाती है कि इसकी बढ़वार नीचे की ओर अधिक हो।

जल निकास

बाजरे की फसल यदि काफी देर तक पानी खड़ा रहे, तो इससे फसल को काफी नुकसान पहुंचता है। इसलिए बुवाई से पूर्व खेत को समतल कर लेना चाहिए

अमरबेल का नियंत्रण

प्रसारण

- परजीवी के बीज एवं तने के भाग सिंचाई करने से जल द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में चले जाते हैं।
- खाद द्वारा भी बीज खेत में आ जाते हैं।
- तने के टुकड़ों का स्थानांतरण मनुष्यों एवं जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दिया जाता है।
- इसके बीज बरसीम, रिजका के बीजों के साथ जुड़े रह सकते हैं।

हानि

अमरबेल के संक्रमण से मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों प्रकार से हानि होती है-

- नींबू में 30-35 प्रतिशत
- मूंग में 70-90 प्रतिशत
- उड़द में 30-40 प्रतिशत
- रिजका, बरसीम में 60-70 प्रतिशत तक उपज में हानि होती है।

नियंत्रण

इस परजीवी पादप के नियंत्रण हेतु समन्वित प्रबंध करना अति आवश्यक है-

नियंत्रण के उपाय

- नमक के 10 प्रतिशत (1 लीटर पानी में 100 ग्राम) घोल में बीजोपचार करके फसल के बीजों की बुवाई करें।
- अमरबेल के बीज रहित फसल के बीज ही बुवाई के काम लें।
- कृषि यंत्रों व पशुओं को अमरबेल से संक्रमित खेतों से स्वच्छ खेतों में न आने दें।
- अमरबेल से ग्रसित फार्म से कम्पोस्ट खाद तैयार न करें।

शस्य नियंत्रण

संक्रमित पौधों को परजीवी में बीज बनने से पहले उखाड़ कर जला दें।

- कम से कम पांच वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए।
- पाश फसलें जैसे ग्वार आदि उगाना चाहिए इसकी बढ़वार कम होगी।
- फसलों की सहनशील किस्में जैसे रिजके की एलएलसी 6 व एलएलसी 7, मूंग की एम-4 व उदड़ की टी-9 किस्में बोनी चाहिए।

जैविक नियंत्रण

मैलेनाग्रोमाइजा करुक्यूटा व कालेटोट्राइकम ग्लोइयोस्पोरीयोडीस के द्वारा भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं।

- ल्यूबाओ-2 जो कि कोलेटोट्राइकम ग्लोइयोस्पोरीयोडिस करुक्यूटी रोगजनक का उत्पाद है, से भी जैविक नियंत्रण कर सकते हैं।

रासायनिक नियंत्रण

- क्लोरोफॉम 6-7 किग्रा (सक्रिय तत्व) या डाइक्लोनेनील 2 किग्रा (सक्रिय तत्व) प्रति हेक्टेयर मिट्टी में प्रयुक्त करें।
- खड़ी फसल (रिजका व बरसीम) में कटाई के 5-10 दिन बाद डाइकव्ट 6-10 किग्रा प्रति हेक्टेयर आवश्यकतानुसार पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
- पेड़ों तथा बहुवर्षीय बेलों पर पेराक्वाट के 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव करें। तथा उपचारित परपोषी पौधों की जल्दी सिंचाई करें।
- यदि अमरबेल पर छिड़काव के बाद कोई अवशेष बच जाये तो पुनः बताये शाकनाशियों का छिड़काव करें।

इकाई क्षेत्र में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हेतु वर्ष 1983 में फादर हेनरी द्वारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेसीफिकेंशन का उद्भव मेडागास्कर में किया गया। इस पद्धति से 7-15 टन धान प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जा सकता है।

धान की मेडागास्कर खेती

भारत में हरित क्रांति आने के बाद से लेकर अब तक विभिन्न आदानों की इकाई लागत में काफी वृद्धि हुई है इस वृद्धि के फलस्वरुप शुद्ध लाभ भी कम प्राप्त हो रहा है, इस हेतु यह आवश्यक हो गया है कि इकाई क्षेत्र में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाये। इकाई क्षेत्र में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हेतु वर्ष 1983 में फादर हेनरी द्वारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेसीफिकेंशन का उद्भव मेडागास्कर में किया गया इस पद्धति से 7-15 टन धान प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जा सकता है।

मेडागास्कर विधि की कृषि कार्यमाला

खेत का चुनाव-मेडागास्कर विधि से धान की खेती करने हेतु उचित जल निकास वाली भूमि का चुनाव करना चाहिए तथा सिंचाई की भी व्यवस्था खेत पर होना चाहिए। बीज की मात्रा-इस विधि से धान की रोपाई करने के लिए 10-12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर पड़ती है।

धान की उन्नत किस्में

कम अवधि में पकने वाली किस्में-तृप्ति, पूर्वा, जेआर 75
मध्यम समय में पकने वाली किस्में-जेआर 201,दीप्ति, जेआर 353
सामान्य अवधि में पकने वाली किस्में-आई.आर. 36, आई.आर. 64, माधुरी,पूसा सुगंधा
देर से पकने वाली किस्में :-स्वर्णा, श्यामला, महासुरी
संकर किस्में-एपीएचआर-1, एपीएचआर-2, एमजीआर-1, सीएनआर एच-1, पंत संकर धान

नर्सरी हेतु खेत की तैयारी एवं बीज की बुवाई

खेत की अच्छी तरह आड़ी-तिरछी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए तत्पश्चात एक मीटर चौड़ी 10 मीटर लम्बी 15 सेमी ऊंचाई की क्यारी बना लें, क्यारी के दोनों ओर सिंचाई नाली बनाये क्यारी तैयार कर 50-60 किलोग्राम नाडेप कम्पोस्ट मिलाकर समतल कर दें तैयार क्यारी में उपचारित बीज को बिखेर दें तथा ऊपर से कम्पोस्ट खाद की पतली परत बिछाकर बीजों को ढ़क दे बीज का उपचार कर ही क्यारी डालना चाहिए। बीज उपचार हेतु स्युडोमोनास फ्लोरोसेंस 3 ग्राम प्रतिकिलो बीज की दर से उपयोग करना आवश्यक होता है। प्रति क्यारी 120 ग्राम बीज की मात्रा या 12 ग्राम प्रति वर्ग मीटर बीज की रोपणी डालने की आवश्यकता होती है। रोपणी की बोनी उपरांत प्रथम सिंचाई हजारे से की जाना चाहिए, शेष सिंचाई रोपणी के दोनों तरफ उपलब्ध सिंचाई नाली से करना चाहिए।

रोपाई हेतु खेत की तैयारी

रोपाई किये जाने वाले खेत की अच्छी तरह जुताई कर भुरभुरा कर लें तथा खेत में पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए। तथा खेत में 8-10 टन नाडेप कम्पोस्ट/गोबर की पकी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। इस प्रकार रोपणी के लिए खेत तैयार हो जायेगा। सामान्यतः 10-15 दिन की पौध इस पद्धति में रोपाई हेतु उपयुक्त होती है। इन पौधों को जड़ सहित सावधानीपूर्वक उखाड़ कर 20 से 30 मिनट के अंदर खेत में रोप देना चाहिए। रोपाई एक से दो सेमी गहराई पर करें तथा पौध को खेत में सीधा रोपना चाहिए। रोपाई के समय खेत में पानी भरा नहीं होना चाहिए। एक स्थान पर एक ही पौधे की रोपाई करें तथा पौध से पौध की दूरी 25 सेमी एवं कतार से कतार की दूरी 23 सेमी रखना चाहिए, जिससे कंसे अधिक संख्या में निकलते हैं।

खाद उर्वरक की मात्रा

खेत की मिट्टी का परीक्षण कराकर तत्वों की उपलब्धता जानने के बाद ही खाद की मात्रा निश्चित की जानी चाहिए, इस विधि में कार्बनिक खादों एवं रासायनिक खादों का उपयोग करना अनिवार्य है चयनित खेत में हरी खाद के लिए सनई/ढैंचा की बोनी कर 20-25 दिन बाद मचाई कर मिट्टी में मिला दें तथा 3-4 दिन के लिए छोड़ दें तत्पश्चात रोपाई करें। रासायनिक खाद में 80 किलोग्राम 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति हेक्टर होती है। फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग आधार खाद के रुप में किया जाना चाहिए व नत्रजन का उपयोग तीन किश्तों में 20 प्रतिशत के एक सप्ताह बाद 50 प्रतिशत कंसे फूटने के समय एवं शेष 30 प्रतिशत गभोट के प्रारंभ काल में किया जाना चाहिए। वानस्पतिक वृद्धि अधिक होने पर नत्रजन की मात्रा कम की जा सकती है।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं : धामी

मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक में दिए निर्देश

जयन्त प्रतिनिधि। देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को रोजगार से जोड़ते हुए युवाओं को अपने गांव में ही आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं।

बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग द्वारा विभिन्न जनपदों में आयोजित की जा रही प्रवासी पंचायतों, पलायन निवारण एवं स्वरोजगार जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गई। आयोग के सदस्यों ने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने तथा रिवर्स पलायन को गति देने के संबंध में विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए सभी विभाग अपनी-अपनी विभागीय गतिविधियों और योजनाओं के माध्यम से समन्वित रूप से कार्य करें। विभागीय योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन केवल रोजगार उपलब्ध कराने से नहीं, बल्कि गांवों में बेहतर आजीविका, सुविधाएं और संभावनाएं विकसित करने से संभव होगा। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ परिणामोन्मुखी कार्य करना होगा। बैठक में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी, सदस्य अनिल सिंह शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, राम प्रकाश पैन्यूली, रंजना रावत, सचिव धीराज गर्ब्याल, डॉ0 श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, अहमद इकबाल, अपर सचिव सौरभ गहरवार, अनुराधा पाल, संतोष बडोनी उपस्थित रहे।

हर पात्र मतदाता को सूची से जोड़ने पर जोर

गोपेश्वर। एसआईआर अभियान को प्रभावी, पारदर्शी बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान एसआईआर की प्रगति, नोटिस वितरण, मतदाता मैपिंग, दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण तथा बूथ स्तर पर निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान हर पात्र मतदाता को सूची से जोड़ने पर जोर दिया गया।

बैठक में बताया गया कि जिले में 63,347 नोटिसों के सापेक्ष 63,246 नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2,72,188 मतदाताओं में से 2,61,060 की मैपिंग पूरी हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि पहली बार नोटिस नहीं पहुंचने पर पुनः नोटिस जारी किए जाएंगे।

चमोली के 25 हिमाच्छादित गांवों में स्व-गणना शुरू

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जनपद चमोली में जनगणना-2027 के तहत हिमाच्छादित एवं दुर्गम राजस्व ग्रामों के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनपद की दो तहसीलों के अंतर्गत आने वाले 25 हिमाच्छादित राजस्व ग्रामों में निवासरत नागरिक 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक स्व-गणना कर सकते हैं। इसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक 25 प्रगणक एवं 7 सुपरवाइजर इन गांवों में घर-घर जाकर मैपिंग एवं जनगणना संबंधी कार्य पूरा करेंगे। इस चरण में ज्योतिर्मठ तहसील के अंतर्गत माणा, खिरोंन, भ्यूंडार, तोलमा, बम्पा, गमसाली, नीती, गुरगुटी, मेहरगांव, मलारी, कैलाशपुर, रेवाली चक कुरकुटी, फरकियागाँव, कोसा, जेलम, जुम्मा, लमतोली, कागा लगा द्रोणागिरी, गरपक, द्रोणागिरी, ऊँथ हनुमानचट्टी बेनाकुली, बदरीनाथपुरी शामिल हैं। वहीं चमोली तहसील के अंतर्गत रुद्रनाथ एवं पांगरवासा राजस्व ग्राम शामिल हैं। इन गांवों के नागरिक स्व–गणना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्व-गणना कर सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर जाकर लगभग 40 आसान प्रश्नों की जानकारी स्वयं दर्ज करनी होगी। स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त कोड नंबर को सुरक्षित रखना आवश्यक है। आगामी 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जब प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे, तब यह कोड नंबर प्रगणक को उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे जनगणना प्रक्रिया को सुगम एवं त्वरित रूप से पूरा करने में मदद मिलेगी। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने जनपद के हिमाच्छादित एवं दुर्गम गांवों के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना-2027 की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए निर्धारित अवधि के भीतर स्व-गणना अवश्य पूरी करें।

संक्षिप्त समाचार

पेयजल लाइन टूटी, हाईवे पर बह रहा पानी

कर्णप्रयाग। सिमली बाजार में जल संस्थान की ओर से दशकों पूर्व बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन जगह–जगह क्षतिग्रस्त होने से हाईवे पर पानी बह रहा है। ऐसे में स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।निवासी पवन डिमरी, मनोज कुमार और अशोक खंडूड़ी ने बताया कि करीब चार दशक पुरानी इस पेयजल योजना के पाइपों में जंग लग चुका है। मुख्य बाजार से न्यू मार्केट की ओर जाने वाली लाइन में सोकेट और यूनियन की जगह रबर के पाइप लगाकर अस्थायी जुगाड़ से आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुजरने वाले वाहनों के दबाव से यह पाइपलाइन आए दिन टूट जाती है जिससे सड़कों पर पानी बहने से आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। लोगों ने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों से कई बार नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की गई लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस संबंध में जल संस्थान के सहायक अभियंता डीसी पुरोहित ने कहा कि जल्द सिमली बाजार की पेयजल लाइन को ठीक कर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा।

डीएलएड प्रशिक्षुओं को कार्यशाला में दी एनईपी की जानकारी

नई टिहरी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में डीएलएड प्रशिक्षुओं का पांच दिवसीय थिएटर इन एजुकेशन कार्यशाला समापन हो गई। कार्यशाला में 39 प्रशिक्षुओं ने प्रतिभाग किया। डायट प्राचार्य सुमेर सिंह कैंतुरा ने कार्यशाला में प्रशिक्षुओं को एनईपी के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. सुमन नेगी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालयों में पाठ्यक्रम, शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी को और रुचिकर बनाना है। कार्यशाला में विनोद पेटवाल, डॉ. वीर सिंह रावत, सीमा शर्मा, संजीव भट्ट, नरेश चंद कुमांई, डॉ. राज किशोर, मानसी, ऋतिक राणा, सुष्मिता जोशी, नितिका मौजूद थे।

ग्रामीणों ने हर्षोल्लास के साथ दुबडी पर्व मनाया

थत्यूड़ (टिहरी)। जौनपुर ब्लॉक के ग्राम खंड़ा, पापरा तल्ला, मल्ला, कुआं, मुंदणी, भुयांसारी, दिक्क, किंन्सू, औतण, बंगशील, तेवा, मोलधार सहित अन्य गांवों में दुबडी (दुर्वाअष्टमी) पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पूर्व प्रधान विजेंद्र सजवाण, कृपाल सिंह रावत, महावीर चमोली, रघुवीर नौटियाल, वीरेंद्र दत्त नौटियाल ने बताया के पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुबडी पर्व के बाद क्षेत्र में त्योहार की शुरूआत मानी जाती है।

गांव-गांव पहुंचेगी मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना की जानकारी

चमोली में लगी उद्यमिता की चौपाल, महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनपद में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुक्रवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर के ऑडिटोरियम हॉल में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना-चौपाल (एमएसएमई चौपाल) का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाली स्वायत्त सहकारिता को सहयोग प्रदान करते हुए अंजलि देवी को उद्यम शुरू करने एवं हिलांस भोजनालय के संचालन के लिए 6 लाख की सहायता राशि का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। गोपेश्वर में आयोजित चौपाल में मुख्यमंत्री के संबोधन का वर्चुअल माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस दौरान युवाओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय

उद्यमियों एवं अन्य प्रतिभागियों ने मुख्यमंत्री का संबोधन सुना। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अधिक से अधिक लोगों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जनजागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन 21 अगस्त से 1 सितंबर 2026 तक जनपद के विभिन्न विकासखंडों एवं न्याय पंचायत क्षेत्रों में पहुंचकर युवाओं, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा स्थानीय उद्यमियों को मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगा। यह वाहन गोपेश्वर, मंडल, चमोली, बिरही, हेलंग, जोशीमठ, तपोवन, नंदप्रयाग, घाट, कर्णप्रयाग, सिमली, नारायणबगड़, थराली, देवाल, गैरसैंण, मेहलचौरी एवं पोखरी सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों एवं न्याय पंचायतों तक पहुंचेगा। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, उद्यम विकास, ब्रांडिंग, उत्पाद पैकेजिंग, गुणवत्ता सुधार एवं बाजार से जोड़ने में सहयोग दिया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उन्हें व्यापक बाजार तक पहुंचाने के लिए मार्केट लिंकेज पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दर्जा मंत्री हरक सिंह, प्रेम सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बर्त्वाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, भेषज संघ अध्यक्ष सतेंद्र असवाल, महामंत्री अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, रघुवीर बिष्ट, नंदी राणा, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं, स्थानीय उद्यमी एवं बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

भूधंसाव से मंदिर और शौचालय को बना खतरा

गौचर। बदरीनाथ हाईवे पर कमेड़ा में हो रहे भूधंसाव से पौराणिक शिवालय मंदिर और शौचालय को खतरा बन गया है। कमेड़ा गांव के प्रधान भागवत प्रसाद मैठाणी, शैल बसंतपुर वार्ड की सभासद बंदना राणा, कांग्रेस प्रदेश सचिव मुकेश नेगी, सामाजिक कार्यकर्ता बीरेंद्र राणा, व्यापार संघ अध्यक्ष राकेश लिंगवाल आदि ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और कंपनी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश से बदरीनाथ तक सड़क सुरक्षा कार्यों का निर्माण कर रही भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी छोटे–छोटे पैच में ठेकेदारों को निर्माण कार्य देती है। आरोप लगाया कि यह ठेकेदार घटिया निर्माण कार्य कर रहे हैं।

प्रसव पीड़ा में तड़पती रही हेमा, 10 किमी पैदल पहुंची पगना

पीपलकोटी। निजमुला–पाणा–ईराणी मार्ग पगना गांव से आगे भूस्खलन के कारण बंद होने से निजमुला घाटी के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क बंद होने का सबसे अधिक असर मरीजों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ रहा है।

शुक्रवार को प्रसव पीड़ा से कराह रही ईराणी गांव की हेमा नेगी आशा कार्यकर्ता व परिजनों के साथ दुर्गम रास्ते और उफनते गदेरों से होते हुए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची।

शुक्रवार को हेमा देवी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर अस्पताल ले जाना जरूरी था लेकिन भूस्खलन के कारण सड़क बंद थी। ऐसे में आशा कार्यकर्ता ने परिजनों के साथ मिलकर महिला को पैदल ही पगना गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया।

रास्ते में जगह–जगह गिर रहे पत्थरों और उफनते गाड–गदेरों के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार किया गया। करीब 10 किलोमीटर कठिन पैदल चलने के बाद वह पगना पहुंचे और वाहन की मदद से महिला को जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाया गया।

ग्राम प्रधान दीपा देवी और ग्रामीणों ने विषम परिस्थितियों में आशा कार्यकर्ता की ओर से किए गए प्रयास की सराहना की।

ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में झिंझी पुल की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं बारिश के कारण वैकल्पिक मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे निजमुला घाटी के ग्रामीणों को मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जल्द झिंझी पुल का निर्माण कराने और क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त कर यातायात बहाल करने की मांग की है।

लोगों से की विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पौड़ी गढ़वाल एवं सिविल जज (सीनियर डिवीजन) श्रीमती नाजिश कलीम के निर्देशन में शुक्रवार को जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड खिर्सू के जनता इंटर कॉलेज, जमणाखाल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, किसी भी प्रकार की विधिक समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया।

शिविर के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं एवं जनमानस को निःशुल्क विधिक सेवाओं एवं विधिक सहायता के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श, निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, न्यायालयीन मामलों में आवश्यक विधिक सहायता तथा

मध्यस्थता, सुलह एवं लोक अदालत के माध्यम से विवादों के समाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस अवसर पर नालाशा 2016 के संबंध में भी उपस्थित जनमानस को विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुलभ, किफायती एवं प्रभावी विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को जागरूकता के अभाव अथवा सामाजिक कमजोरियों के कारण उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाना तथा उनके कल्याण, विधिक सशक्तिकरण एवं समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए सहयोगी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना योजना का प्रमुख उद्देश्य है। शिविर में महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकारों, साइबर अपराध से बचाव, नशे के दुष्प्रभाव, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों तथा विभिन्न विधिक एवं कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।

कांग्रेस नेता ने एसडीएम का जताया आभार

जयन्त प्रतिनिधि। सतपुली : एआईसीसी सदस्य एवं कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने शुक्रवार को प्रतिनिधि मंडल के साथ उप जिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य से मुलाकात कर क्षेत्र में बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनका आभार जताया।

राजपाल बिष्ट ने कहा कि आपदा, सड़क हादसे अथवा क्षेत्र की छोटी-बड़ी जनसमस्याओं के मामलों में उप जिलाधिकारी रेखा आर्य लगातार तत्परता से कार्य कर रही हैं। कहा कि किसी घायल मरीज को तत्काल ऋषिकेश पहुंचाने जैसी आपात स्थिति में भी एसडीएम कार्यालय स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाती है। उन्होंने प्रशासन की सक्रियता और संवेदनशीलता की सराहना करते हुए एसडीएम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एसडीएम रेखा आर्य ने कहा कि जनता की सेवा करना उनकी ड्यूटी है। वह निष्ठा और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। प्रतिनिधिमंडल में ग्राम सभा रेड़ा के प्रधान, पूर्व प्रधान बौंसाल विकास रावत, कल्याण सिंह रावत, कीर्ति रावत आदि मौजूद रहे।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

विभाग	Electrical (TRD)	टेंडर नं.	T-07-TRD-MB-26-27
कार्य का नाम	"मुरादाबाद मंडल के शेष बचे खंड में एल.सी. गेटों के इंटरलॉकिंग के संबंध में टीआरडी कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।		
कार्य की अनुमानित लागत(₹)	₹66,71,904.49 (Including GST @18%)		
बिड सिक्योरिटी राशि(₹)	₹1,33,400/-	निविदा प्रपत्र मूल्य(₹)	NIL
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	11.09.2026 at 15:00 Hrs.		
ऑफर की वैधता(दिन)	60 Days	कार्य पूरा करने की अवधि	06 Months
वेबसाइट एवं कार्यालय का पता	www.ireps.gov.in Divisional Railway Manager's Office, Northern Railway, Moradabad.		

निविदा सूचना सं.:Elect/TRD/MB/2026-27/TN-10 दिनांक: 20.08.2026 2915/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

(मुरादाबाद मण्डल) निविदा सूचना

क्र सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु.)	कार्यालय का पता जहाँ से निविदा प्रपत्र जारी किया गया है	बिड सिक्यूरिटी राशि (रु.)	कार्य के पूर्ण करने की समय अवधि	निविदा प्रपत्र जमा करने तथा खुलने की दिनांक व समय	वेबसाइट एवम कार्यालय का पता
1	29/वरिष्ठ मं.वि.अभि./सा./मुरा./2026 यात्रियों की सुविधाओं हेतु स्टेशनों एवं रेलवे क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के संवर्धन से संबंधित विद्युत कार्य, जिसमें LRJ-HW-MOTC-YNRK एवं RWL-DDN सेक्शन में फेसाड लाइटिंग का अतिरिक्त कार्य भी शामिल है।	30263619.52 (जीएसटी सहित)	विद्युत शाखा, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद	605300.00	4 (चार) माह	निविदाये दिनांक 11.09.2026 को 15:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जो उसी दिन 15:00 बजे खोली जायेगी।	वेबसाइट www.ireps.gov.in मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय/ उत्तर रेलवे मुरादाबाद

निविदा सूचना सं. : 28/2026 दिनांक : 20.08.2026 2906/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

स्कूल की छत का एक हिस्सा टूटा, कमरों में भर रहा पानी

गोपेश्वर। विकासखंड नारायणबगड़ के राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय चोपता की जर्जर छत का एक हिस्सा बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण टूट गया। इससे कक्षाओं में पानी भरने लगा। हादसे की आशंका को देखते हुए अभिभावकों ने बच्चों की कक्षाएं पास की धर्मशाला में शुरू करवाई हैं। मगर धर्मशाला भी सिर्फ 30 सितंबर तक ही उपलब्ध है। ऐसे में इसके बाद 32 छात्र–छात्राओं की पढ़ाई कहां होगी इसे लेकर अभिभावक चिंतित हैं। शुक्रवार को चोपता के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी गौरव कुमार को ज्ञापन सौंपा और समस्या के समाधान की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन कई वर्षों से जर्जर है। इसके बावजूद इसी भवन में पठन–पाठन चल रहा था। 16 और 17 अगस्त को हुई भारी बारिश के दौरान छत का एक हिस्सा टूट गया था। अब बारिश का पानी सीधे कक्षाओं में आने लगा है। भवन की छत अंदर से भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अभिभावकों ने कहा कि सितंबर माह के बाद सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा। उन्होंने

विद्यालय भवन की जल्द मरम्मत कराने या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने ग्रामीणों को बताया कि शिक्षा विभाग को विद्यालय की स्थिति से अवगत करा दिया गया है। जल्द ही बच्चों के लिए उचित व्यवस्था कराई जाएगी। इस मौके पर कनिष्ठ उपप्रमुख भूपेंद्र मेहरा, राखी देवी, आशा देवी, पूनम, ईशा देवी, सुनीता, मीना देवी, अनीता देवी समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

गांव–गांव पहुंचेगी उद्यमशाला योजना की जानकारी

गोपेश्वर। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को महाविद्यालय गोपेश्वर के ऑडिटोरियम में उद्यमिता की चौपाल हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गोपेश्वर में मुख्यमंत्री के संबोधन का वर्चुअल प्रसारण किया गया। इस दौरान योजना के प्रचार–प्रसार के लिए जनजागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह वाहन 21 अगस्त से एक सितंबर तक जिले के विभिन्न विकासखंडों और न्याय पंचायत क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देगा। कार्यक्रम में हरियाली स्वायत्त सहकारिता की अंजलि देवी को हिलांस भोजनालय संचालन के लिए छह लाख रुपये की सहायता का चेक प्रदान किया गया।

गौचर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, सामान भी बरामद

कर्णप्रयाग। कोतवाली पुलिस ने गौचर क्षेत्र में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किए गए जेवरात, सूटकेस और जैकेट भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 6 (निकट केश-ावाइस स्कूल, गौचर) निवासी सत्यपाल सिंह चौधरी ने 20 अगस्त को कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि वह इलाज कराने देहरादून गए थे। वापस आए तो देखा घर का ताला टूटा था और जेवरात व अन्य सामान चोरी हो गया था। पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेद्र सिंह राणा ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में चोरी का

खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के निर्देश पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कर टीम का गठन किया गया। जांच के बाद शुक्रवार को आरोपी उम्मेद सिंह भंडारी (35) निवासी ग्राम कंडारा (कर्णप्रयाग) को गिरफ्तार कर लिया। सीओ त्रिवेंद्र सिंह राणा ने बताया कि आरोपी ने चोरी की बात कबूल की है। जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी पर पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के विभिन्न थानों में चोरी और आर्म्स एक्ट के छह से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें युवा

नई टिहरी। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जीआईसी नागणी में विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया। प्राधिकरण के सचिव दयाराम ने कहा कि शिविर लगाने का उद्देश्य छात्र–छात्राओं को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, सम्मान और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। सचिव ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं, वह अपने अनुभव और योगदान से परिवार और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं।

जयन्त

संस्थापक : नरेन्द्र उनियाल

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से मुद्रित तथा बदरीनाथ मार्ग, कोटद्वार गढ़वाल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित।

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र कोटद्वार, (गढ़वाल) उत्तराखण्ड होगा।

CONT. 9412081969
PRGI NO. 35469/79

श्रीलंका ने कोलंबो टेस्ट के लिए 14 सदस्यीय टीम का किया ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने भारत के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम की घोषणा कर दी है। 14 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर सहन अराचिगे और बल्लेबाज कामिल मिशारा को शामिल किया गया है। पहले टेस्ट के दौरान चोटिल हुए दिनेश चांदीमल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट रहे पासिंदु सोरियाबंदारा को भी टीम से बाहर रखा गया है। दूसरे ओपनर निशान मदुश्का को जगह नहीं मिली, जबकि गेंदबाजी ऑलराउंडर रमेश मेंडिस और तेज गेंदबाज दिलशान मदुश्का भी टीम में जगह नहीं बना सके। अराचिगे को भारत ए के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। अराचिगे ने भारत ए के खिलाफ हाल ही में श्रीलंका ए क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी और बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। अराचिगे ने पहले मैच में 72 और दूसरे मैच में 127 रन की पारी खेली थी। दो अनाधिकारिक मैचों की सीरीज में भारतीय साई सुदर्शन के बाद अराचिगे दूसरे श्रेष्ठ स्कोरर रहे थे। अराचिगे को टेस्ट डेब्यू का इंतजार है। मिशारा लंका प्रीमियर लीग 2026 में शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने हाल के सीजन में नौ पारियों में 411 रन बनाए थे। उन्होंने गॉल गैलेंट्स के खिलाफ शतक भी बनाया था। वे मेजर क्लब्स टी20 कॉम्पिटिशन में शानदार फॉर्म में थे और महज 72 गेंदों पर 145 रन की पारी खेली थी। श्रीलंका पहला टेस्ट मैच हार चुकी है। सीरीज बचाने के लिए श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ जीत दर्ज करनी होगी। पहला टेस्ट टीम इंडिया ने 165 रन से जीता था।

श्रीलंका टीमः

लाहिरू उदारा, कामिल मिशारा, पासिंदू सोरियाबंदारा, कामिंडू मेंडिस (उपकप्तान), धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सहन अराचिगे, सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला, केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, मिलन रत्नायके, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो, विश्वा फर्नांडो।

कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त ने टीम इंडिया और श्रीलंका क्रिकेट टीम की मेजबानी की

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ रविवार से शुरू हो रहे दूसरे टेस्ट मैच से पहले इंडिया हाउस में भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की। भारतीय उच्चायुक्त झा ने गुरुवार रात भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही श्रीलंकाई टीम की भी मेजबानी की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी दी है और इसे एक 'यादगार शाम' बताया है। बीसीसीआई ने अपने एक्स में लिखा, 'कोलंबो में एक यादगार शाम। श्रीलंका में इंडिया के उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले कोलंबो के इंडिया हाउस में भारतीय टीम की मेजबानी की।' झा ने दोनों टीमों की मेजबानी करके खुशी जाहिर की और कार्यक्रम की कुछ झलकियां एक्स पर साझा की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'टीम इंडिया के साथ चीयर कर रहा हूं। श्रीलंका में चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैचों के दौरान भारतीय और श्रीलंकाई पुरुष क्रिकेट टीमों की मेजबानी करके खुशी हो रही है। खेल के लिए एक जैसे जुनून से बंधा, क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच हमेशा रहने वाले रिश्तों को और मजबूत कर रहा है।' भारत ने गाले में पहले टेस्ट में 165 रन की बड़ी जीत के साथ सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। गाले टेस्ट में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 462 रन बनाए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन बनाए थे। श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटकर 178 रनों से पिछड़ी थी। भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रन पर सिमटी और पहली पारी में मिले 178 रन की बढ़त के आधार पर श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया। श्रीलंका दूसरी पारी में 206 रन पर सिमट गई और 165 रन से मैच हार गई। दूसरी पारी में भारत के लिए मानव सुथार ने 6 विकेट लिए थे।

सिनसिनाटी ओपन

इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंची

सिनसिनाटी, एजेंसी। एलेना रयबाकिना को सिनसिनाटी ओपन क्वार्टर फाइनल मैच से बाएं टखने में चोट के कारण बाहर होना पड़ा। इंजरी की वजह से जहां वह टूर्नामेंट से बाहर हो गईं, वहीं उनकी विपक्षी इगा स्वियाटेक सेमीफाइनल में पहुंच गईं। मैच के दौरान स्वियाटेक 4-1 से आगे थीं और रयबाकिना 40-15 पर सर्व कर रही थीं। उसी समय रयबाकिना के लिए मुश्किल शुरू हुई। रयबाकिना नेट पर एक रैली खत्म नहीं कर सकीं। डब्ल्यूटीए की रिपोर्ट के अनुसार, अगले पॉइंट पर उन्हें अपनी पहली सर्व पर पुश करने में मुश्किल हुई, जो सिर्फ तीन शॉट तक चली, और गेम के बीच में मेडिकल जांच के बाद, रयबाकिना ने कुछ देर बाद मैच खत्म करने का फैसला किया। रायबाकिना ने कहा, 'मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सर्व से पुश भी नहीं कर पा रही थी। चलने में दर्द हो रहा है। एमआरआई के बाद समस्या के बारे में और पता चलेगा।' उन्होंने कहा, 'यह मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। कनाडा में बहुत सारे मैच खेलने और यहां लगातार दो मैच खेलने के बाद और मैच से पहले ठीक लग रहा था लेकिन बदकिस्मती से एक गलत मूवमेंट, एक लैंडिंग, और समस्या शुरू हो गई।' बुधवार को चौथे राउंड में सारा बेजलेक

एलेना रयबाकिना इंजरी की वजह से बाहर

सिनसिनाटी ओपन

आर्थर फिल्स ने थियागो अगस्टिन टिरेंटे को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

सिनसिनाटी, एजेंसी। आर्थर फिल्स ने सिनसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फिल्स ने 64 मिनट तक चले मुकाबले में थियागो अगस्टिन टिरेंटे को 6-3, 6-2 से हराया। फिल्स ने इस सीजन के तीसरे एटीपी मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में जगह बनाई है। 22 साल के फिल्स एक सीजन में तीन मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी बन गए। उनसे पहले गाइ फॉरगेट ने 1991 में यह उपलब्धि हासिल की थी। फरवरी में आठ महीने की चोट के बाद वापसी करते हुए फिल्स का शानदार सीजन रहा है। एटीपी जीत/हार इंडेक्स के मुताबिक, इस साल फ्रेंचमैन का टूर-लेवल रिकॉर्ड 30-10 रहा है, जिसमें बार्सिलोना में एक खिताब और मियामी और मैड्रिड में मास्टर्स 1000 इवेंट्स के सेमीफाइनल में पहुंचना शामिल है।

पहले सेट में 4-3 पर एक अहम ब्रेक हासिल करने के बाद, फिल्स ने लगातार जबरदस्त फोरहैंड लगाए, जिससे टिरांटे लगातार बैकफुट पर रहे। एटीपी के मुताबिक, 22 साल के खिलाड़ी ने दूसरे सेट में अर्जेंटीना के खिलाड़ी की सर्विस दो बार तोड़ी और पूरे मैच के दौरान उन्हें कभी भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। अब वह टाइटल मैच में जगह बनाने के लिए फ्लेवियो कोबोली से भिड़ेंगे, दोनों खिलाड़ी अपने करियर में पहली बार मास्टर्स 1000 फाइनल में पहुंचना चाहते हैं।

कोबोली ने घरेलू पसंदीदा टॉमी पॉल के खिलाफ 2-6, 6-3, 6-4 से जीत हासिल की और ओहियो में अपने पहले मास्टर्स 1000 सेमीफाइनल में पहुंच गए। 24 साल के खिलाड़ी अब जून में रोलैंड गैरोस चैंपियनशिप मैच में पहुंचने के बाद अपने पहले सेमीफाइनल की तैयारी करेंगे। वह 2024 और 2025 में जैनिक सिनर के बाद सिनसिनाटी में अंतिम चार में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे इटैलियन खिलाड़ी हैं। पॉल के खिलाफ जीत के साथ, कोबोली ने यह भी पक्का कर लिया कि वह सोमवार को एटीपी रैंकिंग में अपने करियर की नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वह अभी लाइव रैंकिंग में चार स्थान ऊपर चढ़कर नंबर 6 पर हैं।

जैकब मार्टिन को 22 साल पुराने में पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज जैकब मार्टिन को पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 साल पुराने एक मामले में बड़ी राहत दी है। 2004 के इस मामले में कोर्ट ने मार्टिन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर पर फर्जी यूके आव्रजन स्टाम्प, यात्रा व्यवस्था और वित्तीय लेनदेन से जुड़ा आरोप लगाया गया था, जिसे साबित नहीं किया जा सका। अदालत को वित्तीय लेनदेन या अजवा स्पोर्ट्स क्लब पर उनके स्वामित्व या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं मिला। कई गवाह भी इन आरोपों को साबित करने में विफल रहे। मीडिया से बात करते हुए मार्टिन ने बताया कि यह मामला 2004 में उनकी टीम के एक सदस्य द्वारा ब्रिटेन का वीजा समाप्त होने के बाद वहां रुकने और फर्जी आव्रजन स्टाम्प लगवाकर भारत लौटने के बाद शुरू हुआ था। मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था। बाद में उनका नाम मामले में जोड़ दिया गया। घटना के बारे में मार्टिन ने कहा, 2004 में टीम इंग्लैंड खेलने गई थी। जो टीम 2004 में इंग्लैंड गई थी, उसमें से एक लड़के को छोड़कर बाकी सब वापस आ गए। वीजा की वैधता छह महीने की थी, वह छह महीने तक रह सकता था। वह इससे अधिक समय तक रुका रहा। किसी के जरिए उसने वहां फर्जी स्टैंपिंग करवा ली। फर्जी स्टैंपिंग कराने के बाद जब वह भारत वापस आया, तो उसे ब्रिटेन से डिपोर्ट कर दिया गया था। उसे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया और फिर उससे पूछताछ की गई। उन्होंने कहा, 'मेरा नाम एफआईआर में नहीं था, लेकिन जब जांच हुई, तो एक बड़ा नाम होने के नाते मुझे इस मामले में घसीटा गया।

यूएस ओपन 2026: प्राइज मनी में भारी वृद्धि

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा प्राइज मनी बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही है। यूएस ओपन 2026 में खिलाड़ियों की ये मांग पूरी होने वाली है। यूएस ओपन में इस बार खिलाड़ियों के प्राइज मनी में इजाफा होने वाला है। यूएस ओपन की प्राइज मनी में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। खिलाड़ियों की कुल सैलरी बढ़कर 108 मिलियन डॉलर हो गई है। टूर्नामेंट से पहले, यूएसटीए (यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन) ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की। यूएसटीए के सीईओ क्रेग टिली ने कहा कि यह कदम खेल के आगे बढ़ने के लिए जरूरी हो सकता है। यह एथलीटों में कई सालों के निवेश में एक अहम पहला कदम है क्योंकि यूएस ओपन खिलाड़ियों के लिए सबसे अच्छा आर्थिक मौका और खिलाड़ियों, फैंस और पार्टनर्स के लिए टेनिस में सबसे कीमती प्लेटफॉर्म बना हुआ है। एकल विजेता को 52.65 करोड़ मिलेंगे। वहीं, एकल फाइनल में हारने वाले खिलाड़ी को करीब 26.80 करोड़ रुपये (2.8 मिलियन) दिए जाएंगे। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ियों को लगभग 7.46 करोड़ रुपये (780,000) और सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले प्लेयर्स को करीब 13.88 करोड़ रुपये (1.45 मिलियन) मिलेंगे। डबल्स मुकाबलों में पुरुष, महिला और मिक्स जीतने वाले प्लेयर्स को लगभग 9.57 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिन्हें वे आपस में बाटेंगी। वहीं उपविजेता टीमों को करीब 5,00,000 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। इसके अलावा, व्हीलचेयर सिंगल्स के चैंपियन्स को लगभग 99 लाख रुपये (1,04,000) की इनामी राशि मिलेगी। पहले ही मैच में हारकर बाहर होने वाले खिलाड़ी को भी लगभग भारतीय रुपये में 1.34 करोड़ रुपये (140,000) मिलेंगे। यूएस ओपन रोमांचक होने वाला है। पिछले 4 महीने से पेशेवर टेनिस से दूर रहे पूर्व चैंपियन कार्लोस अल्काराज अपना खिताब बचाने के लिए उतरेंगे। अल्काराज ने अप्रैल के बाद से एक भी मैच नहीं खेला है। उन्हें बार्सिलोना ओपन के दौरान कलाई में चोट लग गई थी। चोट की वजह से वह फ्रेंच ओपन, विंबलडन और कई दूसरे टूर्नामेंट से भी बाहर रहे। यूएस ओपन 2026 की शुरुआत 23 अगस्त से होगी और 13 सितंबर को पुरुषों के फाइनल के साथ खत्म होगा।

डोपिंग को लेकर नाडा की बड़ी कार्रवाई, इस भारतीय भाला फेंक एथलीट पर लगाया 10 साल का प्रतिबंध

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने डोपिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई की है। ओलंपियन भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्व एशियाई रजत पदक विजेता और ओलंपियन भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पर दूसरे डोपिंग अपराध के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) के अनुशासनात्मक पैनल ने 10 साल का प्रतिबंध लगाया है। शिवपाल प्रतिबंधित पदार्थ मेथाएंडिएनोन के सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। 31 साल की उम्र में यह प्रतिबंध उनके खेल करियर का अंत कर सकता है। शिवपाल ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

पहले लगा था चार साल का प्रतिबंध

नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने अगस्त 2022 में उन्हें डोपिंग उल्लघंन का दोषी मानते हुए 2021 से चार साल का प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 2025 तक चलना था, लेकिन शिवपाल ने नाडा के अपील पैनल के सामने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि उनकी डोप जांच में पॉजिटिव आने के पीछे दूषित सप्लीमेंट्स जिम्मेदार थे। जनवरी 2023 में अपील पैनल ने उनकी दलील स्वीकार करते हुए प्रतिबंध को चार साल से घटाकर सिर्फ एक साल कर दिया।

एशियाई चैंपियनशिप में जीता था रजत

शिवपाल के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीतना है। दोहा में उन्होंने 86.23 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह पदक हासिल किया था। हालिया मामलों में कार्रवाई का सामना करने वाले शिवपाल अकेले भारतीय एथलीट नहीं हैं। धाविका एमवी जिल्ना को भी दूसरे डोपिंग उल्लघंन के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया गया और वह मेफेंटरमाइन के लिए पॉजिटिव मिलीं। इससे पहले 2021 में शिवपाल का डोप नमूना प्रतियोगिता से बाहर की गई जांच में एक स्टेरॉयड के लिए पॉजिटिव आया था।

कट शॉट बना यशस्वी जायसवाल का 'दुश्मन', 27 गेंदों में 4 बार फंसे...कोलंबो टेस्ट से पहले की गंभीर तैयारी

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के एसएससी मैदान में 23 अगस्त (रविवार) से होना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले यशस्वी जायसवाल अपनी एक खास कमजोरी पर जोरदार मेहनत कर रहे हैं. भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है. मुकाबले से दो दिन पहले यशस्वी जायसवाल ने नेट्स में अपनी उस कमजोरी पर खास तौर पर काम किया, जो गॉल टेस्ट में फिर सामने आई थी. ऑफ स्टंप के बाहर तेज गेंदबाजों की गेंद पर कट शॉट खेलने की उनकी आदत इन दिनों परेशानी बनती दिख रही है. भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल अब तक 30 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन्होंने हर टेस्ट अलग-अलग मैदान पर खेला है. टेस्ट डेब्यू से लेकर अब तक उनका सफर कैरेबियाई देशों, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड और अब श्रीलंका तक पहुंच चुका है. सिर्फ तीन साल के टेस्ट करियर में ही जायसवाल भारतीय बल्लेबाजी की अहम कड़ी बन चुके हैं. सफेद गेंद क्रिकेट वाली उनकी आक्रामकता

नेट्स में शुरू हुआ सुधार का काम

जायसवाल के गलत शॉट खेलने का प्रतिशत भी बढ़ा है. पहले यह आंकड़ा 31.1 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 48.1 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यही वजह रही कि शुक्रवार को कोलंबो के स्पष्ट मैदान पर भारत के तेज गेंदबाजों ने नेट्स में उन्हें लगातार इस एरिया में परखने की कोशिश की.

कट शॉट बना परेशानी की वजह?

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के तेज गेंदबाज फर्नांडो ने जायसवाल को ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद पर फंसाया. जायसवाल गेंद को कट करने के लिए गए, लेकिन किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर डिकवाला के पास चली गई. आंकड़े बताते हैं कि तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलते हुए आउट होने का पैटर्न हाल के महीनों में बढ़ा है. पिछले साल अक्टूबर में भारतीय घरेलू टेस्ट सीजन शुरू होने के बाद से जायसवाल सिर्फ 27 गेंदों में तेज गेंदबाजों के खिलाफ कट शॉट खेलने के प्रयास में चार बार आउट हो चुके हैं. वहीं टेस्ट डेब्यू से लेकर पिछले साल इंग्लैंड दौरे तक, करीब दो साल के दौरान वह 190 गेंदों में सिर्फ चार बार इस शॉट पर आउट हुए थे. यानी हाल के समय में यह कमजोरी ज्यादा साफ होकर सामने आई है.

बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप

त्रिसा-गायत्री ने दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी को हराया, महिला डबल्स में मेडल पक्का

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में उलटफेर करते हुए दुनिया की नंबर 4 चीनी जोड़ी जी यिफान और झांग शुक्सियन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। त्रिसा-गायत्री की जीत ने देश के लिए मेडल पक्का कर दिया है। भारतीय जोड़ी ने एक गेम पीछे रहने के बाद चीनी जोड़ी पर 16-21, 21-15, 21-13 से जीत दर्ज की और महिला डबल्स में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली दूसरी जोड़ी बन गई। इससे पहले महिला डबल्स में 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा ने कांस्य पदक जीता था। शुरुआत में भारतीय जोड़ी कमजोर दिखी क्योंकि जिया और झांग ने 6-2 की बढ़त बना ली और शुरुआती गेम तक अपनी बढ़त बनाए रखी। त्रिसा और गायत्री ने धीरे-धीरे अपनी आक्रामक रिदम पाई, अपने पावरफुल स्मैश और नेट के दम पर अंतर को 8-9 कर दिया। हालांकि, रिकवरी इतनी नहीं थी कि चीनी खिलाड़ी को 11-8 की बढ़त के साथ ब्रेक में जाने से रोका जा सके और आखिरकार शुरुआती गेम 21-16 से जीत लिया। दूसरे गेम भारतीयों ने अपने विरोधियों को वैसा नियंत्रण नहीं करने दिया, लंबी रैलियों में उनका मुकाबला किया और दबाव में डिफेंड करते हुए इंटरवल पर 11-10 की मामूली बढ़त हासिल की। वहां से, त्रिसा और गायत्री और ज्यादा आक्रामक हो गईं। उनके क्रॉस-कोर्ट अटैक ने बार-बार चीनी जोड़ी को कोर्ट के पार खींचा, जबकि उनके डिफेंस ने जिया और झांग के दबाव को झेला। इंडियन्स ने 17-14 की बढ़त के साथ शुरुआत की और फिर गेम 21-15 से खत्म करके निर्णायक बना दिया। निर्णायक गेम में 4-4 से बराबरी की शुरुआत के बाद, त्रिसा ने एक जोरदार स्मैश से ब्रेकथ्रू पाया, और भारतीय जोड़ी ने बढ़त बना ली। लगातार सात पॉइंट्स ने मैच का पासा पलट दिया, जिससे वे 4-4 से 9-4 पर आ गए। त्रिसा के अटैक ने चीनी जोड़ी को नुकसान पहुंचाना जारी रखा। भारतीय जोड़ी ने 11-5 की बड़ी बढ़त के साथ इंटरवल में एंट्री की। साइड बदलने के बाद, जिया और झांग ने थोड़ी देर के लिए अपनी चुनौती को फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने लगातार तीन पॉइंट्स जीतकर अपनी लय वापस पा ली। चीनी जोड़ी पर बढ़ते दबाव के साथ, उनके गेम में गलतियां होने लगीं। 18-9 पर, भारतीय बस बराबरी पर थे। झांग के शॉट को आउट दिए जाने के बाद एक समीक्षा से नतीजे में ज्यादा बदलाव नहीं आया। चीनी जोड़ी की दो और गलतियों ने त्रिसा और गायत्री को निर्णायक पाइंट दिला दिए। इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी का पदक पक्का हो गया।